भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2005

सं0 310–3(1)/2003–इको.– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (बी) (i) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) एतद्द्वारा दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करता हैः

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(i) इस आदेश का नाम "दूरसंचार टैरिफ (उन्तालीसवाँ संशोधन) आदेश, 2005" (2005 का 6) होगा।

(ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में :

(i) खण्ड 3 में शब्द तथा संख्या 'अनुसूची I' के बाद संख्या 'IX' के स्थान पर संख्या 'X' प्रतिस्थापित किया जाएगा, और

(ii) अनुसूची 'IX' के बाद, निम्नलिखित नई अनुसूची जोड़ी जाएगी :

<u>अनुसूची X</u>

<u>अन्तरराष्ट्रीय निजी लीज सर्किट (आईपीएलसी)–(हॉफ सर्किट)</u>

	मद	टैरिफ
(1)	कार्यान्वित किए जाने की तारीख	16.09.2005
(2)	कवरेज	(क) सभी टैरिफ अधिकतम सीमा के रूप में विनिर्दिष्ट (ख) इस अनुसूची के क्रम सं. 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक क्षमता के मामले में टैरिफ की निर्धारित अधिकतम सीमा सभी ऐसे गंतव्यों तथा वॉयस अथवा डाटा के वहन के लिए सभी किस्म की केबल प्रणालियों पर लागू होगी। (ग) सेवा प्रदाता टैरिफ की अधिकतम सीमा में रियायत प्रदान कर सकते हैं। रियायत, यदि प्रस्ताव किया जाता है, तो पारदर्शी, निर्धारित मानदण्ड पर आधारित गैर–भेदभावपूर्ण होनी चाहिए और इनके बारे में ट्राई को सूचित किया जाना चाहिए। (घ) अन्तरराष्ट्रीय निजी लीज सर्किट सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे ऐसे सभी रूटों/गंतव्यों के लिए हॉफ सर्किट का भी प्रस्ताव करें जिनके लिए उन के द्वारा सर्किटों का प्रस्ताव किया जाता है।
(3)	आईपीएलसी के लिए टैरिफ	क्षमता/गति — प्रतिवर्ष टैरिफ की अधिकतम सीमा (रुपए लाख में)

क्षमता/गति	प्रतिवर्ष टैरिफ की अधिकतम सीमा (रुपए लाख में)

		ई–1	13 डीएस–3	104 एसटीएम–1	299
(4)	**ई–1 से कम क्षमता/गति के लिए टैरिफ**	प्रविरिति
(5)	**सैटेलाइट मीडिया के माध्यम से आईपीएलसी के लिए टैरिफ**	प्रविरिति
(6)	**आईपीएलसी से संबद्ध सभी अन्य मामले**	प्रविरिति

<u>सामान्य</u>

इस आदेश के किसी प्रावधान के संबंध में संदेह उत्पन्न होने की स्थिति में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

इस आदेश के अनुबंध–क में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में संशोधन करने का कारण स्पष्ट किया गया है।

आदेशानुसार

(एम. कन्नन)

सलाहकार (आर्थिक)

अनुबंध 'क'

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केबल आधारित अन्तरराष्ट्रीय प्राइवेट लीज सर्किट ग्लोबल (आईपीएलसी) जो सबमेरीन केबल के जरिए ग्लोबल कनेक्टिविटी की पेशकश करता है, ब्राडबैंड तथा इन्टरनेट सेवाओं, अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी की वॉयस टेलीफोनी तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) जैसे कई महत्वपूर्ण उद्योगों तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन है। ये उद्योग इस समय देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं और उन्हें देश के भावी सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। अतः यह जरूरी है कि जिन कीमतों पर उपायोगकर्ताओं को आईपीएलसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं वे प्रतिस्पर्धा के आधार पर निर्धारित हों।

घरेलू बैंडविड्थ के टैरिफ दो बार निर्धारित किए गए हैं

2. यह देखते हुए कि बैंडविड्थ घरेलू तथा अन्तरराष्ट्रीय दोनों की लागत ब्राडबैंड तथा इन्टरनेट सेवाओं को मुहैया कराने की लागत का एक बड़ा भाग है, इसलिए प्राधिकरण ने 21.4.2005 को अधिसूचित अपने टैरिफ आदेश (36वां संशोधन) के माध्यम से घरेलू बैंडविड्थ में अधिकतम टैरिफ संशोधित किए। एसटीएम–1 के मामले में घरेलू लीज सर्किट के संशोधित अधिकतम टैरिफ तब बाजार में मौजूद दर से 70% कम किए गए तथा डीएस–3 के मामले में टैरिफ में बाजार में मौजूद दर से 67% तक की कमी की गई। अन्य क्षमताओं के मामले में कमी अलग–अलग थी। यह उल्लेखनीय है कि घरेलू लीज सर्किट के अधिकतम टैरिफ निर्धारित करने का यह दूसरा अवसर है। जब पहली बार 1999 में अधिकतम टैरिफ निर्धारित किए गए थे तो कुछ क्षमताओं में तब मौजूद टैरिफ में 90% तक की कमी की गई थी।

आईपीएलसी सेवाओं में मार्केट की विफलता

3. प्राधिकरण को उपयोगकर्त्ताओं से ऐसे सिगनल प्राप्त हुए कि आईपीएलसी (सबमेरीन केबल आधारित) के लिए बाजार पर्याप्त प्रतिस्पर्धी नहीं है। वास्तव में प्राधिकरण को नैस्सकॉम, इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसो. ऑफ इंडिया (आईएसपीएआई) तथा अन्य बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) यूनिटों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें आईपीएलसी के टैरिफ को इस आधार पर विनियमित करने का अनुरोध किया गया था कि भारत में आईपीएलसी के टैरिफ कई अन्य देशों से काफी ज्यादा हैं। इन्कमबेंट अर्थात् वीएसएनएल, जिसके पास आईपीएलसी बाजार का एक काफी बड़ा हिस्सा है और जो 5 केबल लैंडिंग स्टेशनों में से 4 में पूर्ण नियंत्रण रखता है, के साथ टैरिफ में कमी करने के लिए प्रोटेक्टेड विचार–विमर्शों का कोई नतीजा नहीं निकला। अतः आईपीएलसी के लिए अधिकतम टैरिफ निर्धारित करने के लिए अप्रैल, 2004 में एक परामर्श पत्र (2004 का 10) जारी करके परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई और उसके बाद जुलाई, 2004 में दिल्ली तथा बंगलौर में ओपन हाऊस विचार–विमर्श किए गए।

बहुत से स्टेकहोल्डरों ने टैरिफ विनियम की इच्छा व्यक्त की

4. परामर्श पत्र पर अधिकतम स्टेकहोल्डरों की राय थी कि अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी (आईएलडी) सेक्टर को 2002 में खोल दिए जाने के बावजूद अभी आईपीएलसी के व्यवसाय में प्रभावी प्रतिस्पर्धा नहीं बन पाई है इसलिए उनकी राय थी कि प्राधिकरण को न केवल आईपीएलसी के टैरिफ विनियमित करने चाहिए बल्कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए और कदम भी उठाने चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आईपीएलसी के लिए लागत आधारित टैरिफ के परिणामस्वरूप उपचित लाभ भी बढ़ेगा, जिससे इंटरनेट तथा ब्राडबैंड सेवाओं की पैठ भी बढ़ेगी। ब्राडवैंड को बढ़ावा देना इस समय सरकार का प्रमुख उद्देश्य है, जैसा कि सरकार की ब्राडबैंड नीति, 2004 में उल्लेख है। यह ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक अवसरों में आधारभूत परिवर्तन लाने का आधार भी मुहैया कराता है। इसके

लिए जरूरी है कि उपभोक्ताओं के लिए सेवा की कीमत वहनीय हों। परामर्शपत्र पर स्टेकहोल्डरों की विभिन्न टिप्पणियों का सार **अनुबंध क के परिशिष्ट 1** में दिया गया है।

प्राधिकरण ने टैरिफ के विनियमन का औचित्य समझा

5. परामर्श की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकरण ने आईपीएलसी के लिए भारत में मौजूद बाजार की स्थितियों, जिसमें कीमत, इसकी मार्केट संरचना, आईपीएलसी की कीमतों सहित, इस क्षेत्र में अन्यत्र मौजूद स्थिति तथा अन्य क्षेत्रों में आईपीएलसी को शासित करने वाले व्यवहार भी शामिल हैं, पर विचार किया। प्रतिस्पर्धा की स्थिति तथा वे कारक, जिनसे भारत में आई पी एल सी बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है, **अनुबंध–क के परिशिष्ट 2** में दिए गए हैं। अन्तरराष्ट्रीय बेंचमार्क की तुलना में भारतीय आईपीएलसी टैरिफ की तुलना **अनुबंध–क के परिशिष्ट 3** में दी गई है। इसके अलावा, प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि आई पी एल सी सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता (अर्थात् एकीकृत रूप से काम करते हैं) भी हैं और इस प्रकार वे ऐसे अन्य स्टैंडअलोन इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ के साधनों का उपयोग करते हैं। इसीप्रकार, ऐसे आईएलडीओ, जिनके पास अन्तरराष्ट्रीय क्षमताएं हैं और जो आई पी एल सी सेवाएं भी प्रदान करते हैं, वे अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी के टेलीफोनी भी मुहैया कराते हैं और जिस सीमा तक आईएलडीओ के पास अन्तरराष्ट्रीय क्षमताएं नहीं होती हैं उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों की सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इन कारकों तथा आई पी एल सी के लिए भारतीय बाजार के संभावित विकास को देखते हुए, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह अधिदेश देने की तत्काल आवश्यकता है कि आई पी एल सी की अधिकतम निर्धारित कीमत प्रमुखत: लागत आधारित हो। इस प्रकार इस उपाय से उद्योग में समान अवसर का वातावरण बनेगा।

अधिकतम टैरिफ का निर्धारण

6. प्राधिकरण ने 11.3.2005 के दूर संचार टैरिफ (चौंतीसवां संशोधन) आदेश 2005 के द्वारा आई पी एल सी (हॉफ सर्किट) के अधिकतम टैरिफ निर्धारित किए और इन्हें 1.4.2005 से लागू किया गया। आईपीएलसी (हाफ सर्किट) के लिए तीन अलग–अलग क्षमताओं अर्थात ई–1, डी एस–3 तथा एसटीएम–1 के वार्षिक अधिकतम टैरिफ – क्रमश :13 रूपए, 104 लाख रुपए तथा 299 लाख रुपए निर्धारित किए गए। विनिर्दिष्ट क्षमताओं के लिए यह निर्धारित अधिकतम टैरिफ वॉयस अथवा डाटा के वहन के लिए सभी गंतव्यों, क्षमताओं, केबल प्रणालियों की किस्मों के लिए लागू की गई थी। ई–1 से कम क्षमता/गति के टैरिफ में प्रविरिति रखी गई थी अर्थात इसे बाजार की शक्तियों के ऊपर छोड़ दिया गया था। इस अधिकतम टैरिफ का आकलन इन्कमबैंट द्वारा आपूर्तित लागत डाटा के आधार पर किया गया।

टैरिफ के निर्धारण का दृष्टिकोण/पद्धति

7. पृथक लेखे लागू किए जाने के बाद, वीएसएनएल द्वारा लेखा पृथक्करण विनियम के भाग के रूप में मुहैया किए गए आँकड़ों का इस्तेमाल लागत अनुमान की गणना का आकलन करने के लिए किया गया। टाप डाउन, पूर्णतः आबंटित लागत (पुरानी लागत के साथ)दृष्टिकोण का इस्तेमाल संगत लागत अनुमान प्राप्त करने के लिए किया गया और इसके लिए वीएसएनएल के पृथक लेखों के लागत आंकड़ों का उपयोग किया गया। यद्यपि, अधिकांश विनियामकों द्वारा टेरिफ का आकलन करने के लिए फारवर्ड लुकिंग लांग रन इन्क्रीमेटल कास्ट (एफएलएलआरआईसी) का इस्तेमाल किया जाता है, परन्तु प्राधिकरण ने एफएलएलआरआईसी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यह समझा गया कि इस प्रकार के दृष्टिकोण से बाजार को बड़ा धक्का लगेगा और ऐसा करने से प्रतिस्पर्धा और कठिन हो सकती है। इसका आशय यह है कि अधिकतम कीमत के आकलन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले लागत आधार में बफर मौजूद है, इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लागत आधारित टैरिफ, भारत में आईएलडीओएस द्वारा हाल ही में अधिग्रहीत

सबमेरीन केबल प्रणालियों की लागत/निवेश के बहुत कम स्तर पर आधारित नहीं थे। इन लागतों का इस्तेमाल करने से आईपीएलसी के लागत आधारित टैरिफ में भारी कमी हो गई होती और यह अन्तरण की अवधि के दौरान बाजार को कोई बड़ा धक्का पहुंचाए बिना लागत आधारित अधिकतम टेरिफ निर्धारित करने के प्राधिकरण के प्रयासों के विरूद्ध होता। इन्हीं कारणों से प्राधिकरण ने नए प्रवेशकों, जिसमें टाटा इंडिकॉम केबल सिस्टम भी शामिल है, द्वारा मुहैया कराए जाने वाले सबमेरीन केबल आईपीएलसी सेवाओं की लागत का भी इस्तेमाल नहीं किया। प्राधिकरण द्वारा आईपीएलसी के लिए अधिकतम टैरिफ के निर्धारण के लिए इस्तेमाल में लाई गई विस्तृत कार्यविधि तथा लागत की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति **अनुबंध क के परिशिष्ट 4** में दी गई है।

टैरिफ आदेश के संबंध में वीएसएनएल की चुनौती

8. टीटीओ में किए गए 34 वें संशोधन, जिसमें आईपीएलसी (हाफ सर्किट) के अधिकतम टैरिफ निर्धारित किए गए थे, को वीएसएनएल द्वारा 2005 की अपील सं. 5 के द्वारा टीडी सैट में प्रमुखतः इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ट्राई ने उन विभिन्न प्रलेखों तथा सूचनाओं को उजागर नहीं किया, जिनके आधार पर आईपीएलसी के टैरिफ निर्धारित किए गए। टीडीसैट ने अपने 28.4.2005 के आदेश के द्वारा प्रतिवाद आदेश को निरस्त करते हुए यह मामला वीएसएनएल के साथ संगत सामग्री को शेयर करने तथा उनकी फीडबैक को सुनने के बाद पुनर्विचार के लिए ट्राई को भेजा।

प्राधिकरण द्वारा टीडी सैट के अधिदेश के अनुसार सूचना उजागर करना

9. मौजूदा बाजार की हानि वाली संरचना के कारण उपयोगकर्ता उद्योगों तथा उपयोगकर्ताओं को जो आईपीएलसी (हॉफ सर्किट) के लिए ऊँची दर पर टैरिपफ का भुगतान करना पड़ रहा है। उसमें उन्हें तत्काल राहत देने की दृष्टि से ट्राई ने टीडी सैट के निर्देशों का पालन किया और वीएसएनएल के साथ संपर्क कर ई'1 टैरिफ के विस्तृत आकलन के लिए

संबंधित सूचना, लागत आंकड़े तथा उच्चतर क्षमताओं के कीमत अनुपात, रिपोर्टों आदि को शेयर किया। ऐसा उद्योग तथा उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखकर तत्काल आदेश जारी करने के लिए किया गया और ऐसा करते समय पारदर्शिता रखने के संबंध में टीडीसैट के निर्देशों को भी ध्यान में रखा गया। लागत डाटा तथा आईपीएलसी सेवा के लिए लागत की गणना में मैसर्स रिलायंस इन्फोकॉम, मैसर्स भारतीय इन्फोटेल तथा टाटा इंडिकॉम केबल सिस्टम के प्रावधान को बीएसएनएल के साथ शेयर नहीं किया गया क्योंकि आईपीएलसी के लिए अधिकतम टैरिफ का निर्धारण वीएसएनएल की पुरानी लागत के आधार पर किया गया था। सूचना उजागर करने के संबंध में टीडीसैट के आदेश में केवल वीएसएनएल का मामला ही शामिल है और इसमें अन्य मामले शामिल नहीं हैं।

उच्चतम न्यायालय में ट्राई की अपील

10. यद्यपि प्राधिकरण ने टीडी सैट के निर्देशों के अनुसार वीएसएनएल को सूचना उजागर की परन्तु इसने टैरिफ के निर्धारण जैसे कार्यों में अपेक्षित पारदर्शिता तथा टैरिफ के निर्धारण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की व्यावहारिकता से संबंधित बड़े विनियामक मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील सं. 3362/2005 (अब एडमिट) भी दायर की। प्राधिकरण के विचार में ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और विनियामक कार्यों के निर्वहन के लिए इनका तत्काल समाधान किया जाना आवश्यक। ऐसा न करने से विनियामक प्रक्रिया निर्धारित करना प्रभावित होगा।

वीएसएनएल के साथ डाटा/रिपोर्ट शेयर करने की प्रक्रिया

11. सूचना शेयर करने के बाद प्राधिकरण ने वीएसएनएल के विचार सुने। प्राधिकरण द्वारा मुहैया कराए गए इस अवसर का वीएसएनएल ने इस्तेमाल किया और 1.7.2005 तथा 8.7.2005 के दो अवसरों पर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिए। वीएसएनएल ने अलग से भी प्राधिकरण को अभ्यावेदन दिए। वीएसएनएल के अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों पर विचार

किया गया तथा इस आदेश द्वारा अधिसूचित आईपीएलसी के टैरिफ का निर्धारण करते समय इन्हें ध्यान में रखा गया। वीएसएनएल को सभी संगत लागत डाटा, लागत गणना, एर्नेस्ट एण्ड यंग की रिपोर्ट की प्रति आदि देने के अलावा प्राधिकरण ने वीएसएनएल के दो बार विचार भी सुने जिनमें उन्होंने अपनी प्रस्तुति पेश की। इसके अलावा ट्राई द्वारा वीएसएनएल की लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों की सत्यापन रिपोर्ट भी उनको दी गई और उनसे इस बारे में टिप्पणी प्राप्त की गई। इसके बाद वीएसएनएल से प्राप्त उत्तर की जांच की गई और इस पर प्राधिकरण की राय और संशोधित गणना का ब्यौरा भी वीएसएनएल को दिया गया। वीएसएनएल द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया तथा इन्हें निम्नलिखित खण्डों में दिया गया है।

खण्ड II

आईपीएलसी के विनियम की आवश्यकता के संबंध में वीएसएनएल की राय तथा इसके संबंध में टिप्पणी

12. इस संबंध में वीएसएनएल की राय आईपीएलसी के विनियमन के विरूद्ध हैं और इनमें यह शामिल है कि बैंचमार्किंग के लिए कीमत सूचना की तुलना 'गलत' है तथा समुचित बैंचमार्क का इस्तेमाल करने से पता चलेगा कि भारत में आईपीएलसी की कीमतें प्रतिस्पर्धी हैं।

अन्तरराष्ट्रीय बैंचमार्क, इसकी भूमिका तथा प्रासंगिकता

13. प्राधिकरण ने अन्तरराष्ट्रीय बैंचमार्क तथा अन्य कारकों का इस्तेमाल केवल भारत की स्थिति की तुलना देश के बाहर की स्थिति से करने के लिए किया है। टैरिफ के निर्धारण से इसका कोई संबंध नहीं है, जो लागत पर आधारित है, इसके अलावा, भारत तथा दूसरे देशों के बीच कीमतों की पूरी तुलना के आधार पर प्राधिकरण ने आईपीएलसी सेक्टर में भारत में

टैरिफ विनियमित नहीं किए थे। विनियम इसलिए अपेक्षित है क्योंकि भारत में काफी समय से अन्तरराष्ट्रीय बैंचमार्क की तुलना में तथा साथ ही सेवाओं के प्रावधान की लागत में कमी की तुलना में टैरिफ में कोई बड़ी कमी नहीं की गई है। यह प्राधिकरण के लिए बाजार की विफलता का संसूचक है। इसके अलावा, टी डी सैट का निर्णय इस सेक्टर को विनियमित करने की आवश्यकता पर प्रश्न चिन्ह्न नहीं लगाता । यह प्राधिकरण के इस कार्य पर कोई आपत्ति नहीं करता। इसके बावजूद इस संबंध में वीएसएनएल द्वारा उठाए गए विशिष्ट मुद्‌दों को पूर्णतः ध्यान में रखा गया है, जिन्हें निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है :

वीएसएनएल द्वारा समय अवधि तथा बाजार की गलत तुलना

14. वीएसएनएल ने आईपीएलसी कीमतों की तुलना के लिए तुलना की अवधि का विरोध किया और मांग की कि तुलना 2002 के बजाय 2000 से की जानी चाहिए। प्राधिकरण द्वारा भारत में आईपीएलसी कीमतों के रूझान तथा 2002 से इन सेवाओं की अन्तरराष्ट्रीय कीमत से तुलना करना उचित है। तुलना के लिए वर्ष 2002 महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि इसी वर्ष आईएलडीओ सेक्टर प्रतिस्पर्धा के लिए खोला गया तथा वीएसएनएल का स्वामित्व निजी कम्पनी को हस्तान्तरित किया गया। आश्चर्य की बात है कि प्राधिकरण के पास ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे पता चलता है कि इस सेक्टर को प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने के बाद वीएसएनएल के टैरिफ में गिरावट, यदि आई भी है तो वह बहुत ही कम है। वीएसएनएल ने आईपीएलसी की कीमतों की तुलना 2000 से दर्शायी है न कि स्वामित्व के हस्तान्तरण के बाद के वर्ष से जो संयोग से इस सेक्टर का प्रतिस्पर्धा के लिए खोले जाने का वर्ष भी है।

स्वतंत्र रिपोर्टें आईपीएलसी के लिए भारतीय बाजार को न्यूनतम प्रतियोगी के रूप में वर्गीकृत करती हैं।

15. इसके अतिरिक्त, वीएसएनएल ने भारत और इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, मध्य पूर्व आदि देशों जो कि न्यूनतम प्रतियोगी बाजारों वाले देशें के रूप में जाने जाते हैं, के बीच

तुलना करने की मांग की है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि इस संबंध में गार्टनर द्वारा दी गई स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकला है कि भारत में आईपीएलसी का बाजार प्रतियोगिता में पिछड़ रहा है। इस संबंध में गार्टनर की रिर्पोट के निष्कर्षों को नीचे प्रस्तुत किया जा रहा हैः–

'अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ के लिए सबसे अधिक प्रतियोगी बाजार हाँग–काँग, सिंगापुर, जापान, ताईबान और दक्षिण कोरिया हैं। न्यूनतम प्रतियोगी बाजार इंडानेशिया, भारत और मलेशिया हैं'।

(स्रोत : गार्टनर, इंक 2004, " बाजार फोकसः अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ मूल्य रुझान, एशिया–प्रशांत, 2004 ")

जब लक्ष्य प्रतियोगी कार्यकुशलता प्राप्त करना हो, ऐसे समय में वीएसएनएल का यह कहना कि हमें कम प्रतियोगी बाजारों से तुलना करनी है, यह हमारे उद्देश्य के विरूद्ध है।

<u>नजदीकी और दूर के हॉफ सर्किटों के लिए बाजारों की तुलना</u>

16. वीएसएनएल ने यह भी तर्क दिया है कि भारतीय छोर के हॉफ सर्किट ई–1 मूल्य दूरस्थ मूल्यों के अनुकूल हैं। प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर और इस संबंध में वीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पर विचार किया। प्रस्तुत किया गया प्रमाण कुछ चयनित मूल्य सूचियों के रूप में था जिसके साथ संबंधित ब्यौरा संलग्न नहीं किया गया था। इस बारे में यह पुष्टि करना संभव नहीं था कि दूरस्थ क्षेत्रों के वीएसएनएल द्वारा दर्शाए गए मूल्य क्या अतिरिक्त क्षमता की लघु अवधि की आपूर्ति के लिए थे या यह तुलना समान सेवाओं और मानकों के लिए की जा रही थी। वास्तव में **अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ 2005 पर रिपोर्ट** (**प्राईमट्रिका**, इंक,

केलीफोर्निया 2005) ने इस संबंध में प्रमाण प्रस्तुत किया है कि नजदीकी क्षेत्रों की अपेक्षा दूरस्थ क्षेत्रों में बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी है। रिपोर्ट में इस प्रकार उल्लेख किया गया है :–

"2004 में, भारत के मार्गों पर बैंडविड्थ मूल्य अलग–अलग क्षेत्रों में अलग–अलग नहीं है। पूर्ण सर्किट के मूल्य दो आधे सर्किटों के मिश्रण के आधार पर – मुंबई और यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 2004 में बहुत अधिक समान थे। **इस एकरूपता को इस तथ्य पर आधारित माना जा सकता है कि आधे सर्किट का मूल्य कुशलतापूर्वक निर्धारित किया गया था** और प्रतियोगिता से केवल विदेशी आधे सर्किट के मूल्य प्रभावित हुए ।" (बल दिया गया है)

नैसकॉम की जांच का परिप्रेक्ष्य :

17. इस संदर्भ में, वीएसएनएल ने आईपीएलसी टैरिफ के निर्धारण से संबंधित परामर्श पत्र पर नैसकॉम की प्रतिक्रिया का हवाला दिया है। इस मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए प्राधिकरण ने आईपीएलसी के लिए अधिकतम टैरिफ के निर्धारण पर परामर्श पत्र जारी करने से पहले तथा परामर्श पत्र पर प्रतिक्रियास्वरुप नैसकॉम द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमुख टिप्पणियों पर विचार किया। इनका विवरण नीचे दिया गया है :–

- भारत से संयुक्त राज्य अमरिका के लिए एक 45 एम बी / 155 एम बी लिंक की लागत सिंगापुर से इसी प्रकार के लिंक से लगभग दो से तीन गुणा (200–300 %) महंगी है और बड़ी चिंता का विषय है कि यह चीन से 8 से 10 गुणा महंगी है।

- विशेष चिंता का विषय यह तथ्य है कि 2 एम बी लिंक का मूल्य अंतराष्ट्रीय मानकों की अपेक्षा अधिक है, जैसे –जैसे हम 45 एमबी या 155 एमबी की बात करते हैं तो यह अंतर और बढ़ जाता है। **मूल्य गुणक 2 एमबी से 45 एमबी और फिर 155 एमबी तक भारत के लिए लगभग 17 और 53 गुणा है, विदेशों के लिए यह**

क्रमशः केवल 7 और 18 गुणा के लगभग है। अतः इस संबंध में हमारा नुकसान अक्षरशः बढ़ रहा है।

- आधा सर्किट ई–1 (परामर्श पत्र के अनुसार) के लिए प्रस्तावित 12 लाख की टैरिफ के लिए भारत के एक छोर से दूसरे छोर के लिए मूल्य फिलीपींस से तीन से चार गुणा होगा।
- अनुपात निर्धारित करने के लिए उपयोग में लाई गई विधि एक सही दिशा में उठाया गया कदम तथा शुभारंभ है। ई–1, डी एस–3 और एस टी एम'–1 के लिए मूल्य का अनुपात, जिसकी 1:8:23 के रूप में गणना की गई है, निम्न स्तर का होना चाहिए ताकि यह विश्व–व्यापी उद्योग मानकों (जापान–अमेरिका 1:4:10, चीन–अमेरिका 1:5:12, हाँग–काँग–अमेरिका 1:5:11, सिंगापुर–अमेरिका 1:4:9) के अनुरूप बनाया जा सके।
- आईएलडीओ विशेषकर जिनके पास 'इंकमवेंट' सुविधा है उन्हें अन्य आईएलडीओ को घटी दरें प्रस्तावित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि अधिक आदेश क्षमता की आवश्यकता प्रलक्षित हो एवं मार्गविरोध सुविधा में भागीदारी का संवर्धन किया जा सके।
- ट्राई को उद्योग की आवश्यकता के अनुसार लचीलेपन, उच्च एस एल ए तथा भारत को प्रतियोगी बनाए रखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक लागत कटौती प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से मार्गविरोध स्रोतों में भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए।

18. अतः यह स्पष्ट है कि नैसकॉम जैसी मुख्य उपभोक्ता एसोसिएशन का फीडबैक भारत में आईपीएलसी बाजार के विश्लेषण के संदर्भ में प्राधिकरण के कुछ मुख्य निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

19. वीएसएनएल द्वारा यह गलत निष्कर्ष निकाला गया है कि आईपीएलसी के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों की बेंचमार्किंग के लिए प्राधिकरण द्वारा किया गया तुलनात्मक अध्ययन थोक मूल्यों और

फुटकर मूल्यों के बीच है। वीएसएनएल के अनुसार, बेंचमार्किंग के लिए प्राधिकरण द्वारा तुलना किए गए मूल्य विशेषकर उच्च क्षमता के मामले में थोक ट्रांज़िट मात्रा को दर्शाते हैं, अतः यह तुलना अति साधारण है। यह वीएसएनएल द्वारा लगाया गया गलत अनुमान है। यह सभी जानते हैं कि विशेषकर एसटीएम–1 जैसी उच्च क्षमता के संबंध में थोक क्षमता खरीद और आईपीएलसी के फुटकर खरीद में अंतर करना बड़ा कठिन है। इस स्तर के खरीददार अनिवार्य रूप से टेलीकॉम ऑपरेटर या बहुत अधिक मांग रखने वाले विशाल अंतरराष्ट्रीय कंपनियां (टीएनसी) होती हैं। ऑपरेटर और टीएनसी दोनों एक ही बाजार से अपनी क्षमता के अनुसार खरीददारी करेंगे। यदि किसी भी वस्तु को 'केवल थोक उत्पाद' माना जा सकता है तो वह है – वेवलैंथ और/या डार्क फाईबर के लिए बाजार जो कि अतिरिक्त सेवाओं के बिना अंतिम उपभोक्ता के लिए अत्यंत उच्च क्षमता वाले होते हैं। ऐसी क्षमता की बिक्री सामान्य नहीं है और इसे प्राधिकरण द्वारा आईपीएलसी मूल्यों की अंतरराष्ट्रीय तुलना का हिस्सा नहीं माना गया था।

20. यह सिद्ध करने के अपने प्रयास में कि प्राधिकरण द्वारा की गई तुलना उचित नहीं है, वीएसएनएल ने अपने ही परामर्शदाता अर्थात बोस्टन कंसलटिंग ग्रुप (बीसीजी) द्वारा दिए गए आईपीएलसी मूल्यों की अर्नेस्ट एंड यंग रिपोर्ट (टीडीएसएटी के अधिदेशित खुलासे के भाग के रूप में ट्राई द्वारा उनके साथ अंशभागिता) में दिए गए मूल्यों के साथ अनौचित्यपूर्ण तुलना की। यह तुलना अनौचित्यपूर्ण है क्योंकि बीसीजी ने सूचीबद्ध मूल्यों पर विश्वास किया जबकि अर्नेस्ट एंड यंग ने अपने अंतिम विश्लेषण में बाजार मूल्यों को लिया था। ऐसी स्थिति में तुलना के लिए संबंधित मूल्य, बाजार में प्रचलित औसत वास्तविक मूल्य हैं न कि सूचीबद्ध मूल्य।

21. इन्कमबेंट ने प्राधिकरण के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया है कि कतिपय एशियाई देशों में दर्शाए जाने वाले प्रचलित आईपीएलसी के कम मूल्य वास्तव में हबों के बीच के मूल्य है और ऐसे हबों के बीच आईपीएलसी की कीमतें कम ही होगी। मौजूदा परिस्थितियों के अंतर्गत वीएसएनएल का यह दावा पूर्णतः सही नहीं है। जहां कहीं भी विशिष्ट समर्पित लिंक – जैसे

सिंगापुर के लिए लिंक, हैं वहां उपलब्ध क्षमता हब से हब लिंक के परिमाप के अनुसार है। इसके अतिरिक्त, भारत को मुख्य ट्रंक केबल प्रणाली के सीधे मार्ग पर होने का लाभ भी प्राप्त है। वीएसएनएल की ओर से अपनी रिपोर्ट में बीसीजी द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण का "हब–स्पोक" फ्रेमवर्क ऐसे बाजार पर लागू होता है जहां मांग की कमी हो और तदनुरूपी अंतरराष्ट्रीय क्षमता की कमी हो जोकि भारत में डाटा सर्विस की वृद्धि को देखते हुए और अंतरराष्ट्रीय निजी लाइन क्षमता के संवर्धन में वीएसएनएल सहित आईएलडीओ के निवेश को देखते हुए भारतीय बाजार के लिए सच नहीं है। प्राईमट्रिका द्वारा वर्ष 2005, 2006 और 2007 के लिए भारत में अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ का प्रयोग क्रमशः 12.8 जीबीपीएस, 28 जीबीपीएस और 45.9 जीबीपीएस है। भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ का अनुमानित उपयोग (जैसाकि वर्ष 2005 के लिए अनुमानित) थाईलैंड, फीलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, यूएई, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड मिश्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की अपेक्षा अधिक है (स्रोतः प्राइमट्रिका इंक 2005, अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ रिपोर्ट 2005) यह कहने की जरूरत नहीं कि आउटसोर्सिंग उद्योग की बिजनेस प्रक्रिया की सफलता तथा अर्थव्यवस्था की उच्च वृद्धि दर से मांग प्रेरित होती है। इस संबंध में, प्राधिकरण ने पुनः यह नोट किया कि आईपीएलसी के लिए निर्धारित टैरिफ वास्तविक लागत के आधार पर निर्धारित की गई है और उस लागत में भी पर्याप्त गुंजाईश और बफर मुहैया कराया गया है।

केबल मालिकों की कमी के कारण अंतरराष्ट्रीय सबमैरीन बैंडविड्थ मूल्य अन्य बाजारों में सभी मामलों में कम नहीं है।

22. वीएसएनएल का यह तर्क कि अन्य बाजारों में मूल्य मार्ग–विशेष पर आधारित है और अन्य बाजारों में अंतरराष्ट्रीय सबमैरीन बैंडविड्थ का कम मूल्य केबल मालिकों की कमी के कारण है तथा अध्ययन– II के अनुसार दिवालियापन पूर्णतः सही नहीं है। यदि ऐसा था, वीएसएनएल ने यह उल्लेख नहीं किया है कि ऐसे मार्गों पर मूल्य में कमी करने के लिए इतना दबाव क्यों है जो मार्ग ऐसे वाहकों द्वारा सेवित हैं जिनमें कोई परेशानी नहीं है। वास्तव

में, वीएसएनएल (बीसीजी रिपोर्ट) द्वारा मुहैया कराए गए डाटा के अनुसार, ऐसी दिवालिया कंपनियों के लिए क्षमता का एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्राँस–अटलांटिक क्षेत्र में था, न कि दक्षिण, दक्षिण–पूर्व और पूर्व एशिया के लिंक में । इसके अतिरिक्त, आई 2 आई, टी आई सी केबल प्रणाली, एस ई ए–एम ई–डब्ल्यू ई–4 और फॉलकन में हाल ही में किया गया निवेश वीएसएनएल के इस सिद्धांत के विपरीत जाता है कि किसी भी संभावित वसूली के लिए भारत के किसी भी हिस्से में मूल्यों में कमी करना एक मजबूरी है' और इसलिए 'वाहकों का केबल में निवेश किफ़ायती नहीं है'। वीएसएनएल ने वास्तव में यह स्वीकार किया कि "सभी आईएलडीओ संचालक पूरे जोर–शोर से बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और केबल प्रणाली में काफी निवेश कर रहे हैं "। निकट भविष्य (6 से 12 महीने) में यह उम्मीद है कि भारतीय कंपनियां भारत में बिछाई गई विभिन्न नई केबल प्रणालियों में लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डालर का निवेश करेंगी।" (स्रोत : ;भारत में निजी पट्‌टे पर दिए गए अंतरराष्ट्रीय सर्किटों में प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए किए गए उपायों' पर परामर्श पत्र की प्रतिक्रिया में वीएसएनएल का दिनांक 6.7.2005 के 24 का पृष्ठ 11)। अन्ततः वीएसएनएल सहित भारत में ऑपेटर वास्तविक निवेश से अत्यधिक घटी दरों पर उनसे सबमैरिन बैंडविड्‌थ खरीदकर या सोसिग करके विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सर्किट आपरेटरों की दुर्भाग्यपूर्ण वित्तीय स्थिति का लाभ उठा सकने की स्थिति में है। इसे प्राधिकरण की लागत आधारित गणना में शामिल नहीं किया गया है। चूंकि लागत पूर्णतः पुराने आधार पर आबंटित की जा रही है, अतः अन्य बाजारों में ऑपरटरों का दिवालियापन संगत नहीं है।

बाजार का विनियमन निवेश प्रभावित नहीं कराता

23. वीएसएनएल (VSNL) की राय थी की बाजार को विनियमित करने के किसी भी प्रयास से निवेश प्रभावित होगा और इस प्रकार विकास भी अवरूद्ध होगा। उनका यह भी विश्वास था कि इससे ग्राहकों के लिए पैकेजों की पेशकश करने में भी जटिलता आएगी। प्राधिकरण का विचार है कि प्राधिकरण द्वारा अधिकतम कीमत निर्धारित करने से भावी निवेश पर प्रतिकूल

प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्तमान क्षमता का काफी कम उपयोग हो रहा है और जैसा कि नोट में अन्यत्र चर्चा की गई है पुरानी लागत को अपनाने और उन पर लागत अनुमान में बफर मुहैया कराने के कारण लागत अनुमान में पर्याप्त मार्जिन पहले ही मुहैया है। इसके अलावा, यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले कई वर्षों से बहुत उंची कीमत मौजूद होने के कारण इन्कमबेंट ने इन सुविधाओं से भारी राशि अर्जित की है। चूंकि आईपीएलसी की प्रस्तावित कीमतें अधिकतम सीमा के रूप में होगी इसलिए ऑपरेटर अधिकतम निर्धारित सीमा के भीतर उपभोक्ताओं को किसी भी पैकेज की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र हैं।

<u>ब्रॉडबैंड पैनीट्रेशन में आईपीएल का महत्व</u>

24. इसके अतिरिक्त, वीएसएनएल ने यह उल्लेख किया है कि आईपीएलसी की लागत आईटीईएस–बीपीओ इंटरप्राइज़ेज की कुल लागत/राजस्व के प्रतिशत का एक छोटा सा हिस्सा है, अतः टैरिफ विनियमन से इन उद्योगों को कोई विशेष राहत नहीं मिलेगी। प्राधिकरण इस तर्क से दो कारणों से सहमत नहीं है। पहला, टैरिफ विनियमन करके किसी भी उद्योग को राहत पहुँचाने की प्राधिकरण का इरादा नहीं है। दूसरा, आईपीएलसी सेवाओं के लिए आईटीईएस, बीपीओ जैसे प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा अदा किए जाने वाले मूल्यों का खंडित बाजार संरचना के कारण जब तक प्रतिस्पर्धात्मक रूप से निर्धारण नहीं किया जाता, तब तक कुल लागत में इस मद की लागत के सापेक्ष महत्व पर ध्यान दिए बिना मूल्यों के विनियमन की आवश्यकता उठती रहेगी। आईपीएलसी ब्राडबैंड/इन्टरनेट सेवा के लिए एक मुख्य इनपुट है। इस संबंध में, योजना आयोग द्वारा दिए गए दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से यह उद्धृत करना प्रासंगिक है। (स्रोतः http://planningcommission.nic.in/midterm/midtermapp.html) :

"इस दशक के अंत तक सभी नागरिकों तक ब्राडबैंड पहुंचाना प्रत्येक आधुनिक देश और भारत की भी राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए (पैरा 9.2.18–पृष्ठ 300)"

"विकास के लिए और ब्राडबैंड में परिवर्तन लाने के लिए इसे जनता तक आसान पहुंच वाला, सस्ता और लाभदायक बनाना होगा (पैरा 9.2.22–पृष्ठ–301)"

"त्वरित आर्थिक वृद्धि और सामाजिक बदलाव के लिए ब्राडबैंड शीघ्र ही एक पूर्वापेक्षा बनता जा रहा है। ब्राडबैंड आधारित इंटरनेट अनुप्रयोग वास्तव में प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि करने का वचन देते हैं।................ कार्यकुशल और सस्ती ब्राडबैंड सेवाएं अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में भारत के प्रतियोगी लाभ को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होंगी (पैरा 9.2.17–पृष्ठ 300)"

"........अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ की लागत एक और समस्या है जिसका शीघ्र समाधान किया जाना आवश्यक है। अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ की लागत में कमी करने के लिए और इसे सस्ता बनाने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है (पैरा 9.2.22–पृष्ठ 301)"

25. इस संबंध में योजना आयोग ने भी अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ की लागत को काफी कम करने के लिए एक प्रणाली बनाए जाने की वकालत की है।

बाजार में प्रतिस्पर्धा से संबंधित मुद्दों की और जांच

26. वीएसएनएल ने दावा किया है कि जब से आईएलडी सेक्टर प्रतिस्पर्धा में आया, तब से इसने अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बाजार को एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है और अब इसका एकाधिकार समाप्त हो चुका है। इसने यह भी दावा किया है कि भारती और रिलायंस के रूप में बड़े प्रतिस्पर्धी भी हैं जिनके पास आईपीएलसी के बाजार की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है।

27. प्राधिकरण ने यह नोट किया कि इस समय वीएसएनएल भारत में 5 में से 4 केबल लैंडिंग स्टेशनों का नियंत्रण करती है और इस समय वीएसएनएल एकमात्र आईपीएलसी सेवा प्रदाता है जिसने अनेक केबल लैंडिंग स्टेशनों पर नियंत्रण के अलावा पूर्ण रेस्टोरेबल मल्टीपल केबल प्रणालियों की एक्सेस भी है। वीएसएनएल के पास विश्व भर में फैले कई समुद्र में बिछाए गए केबल लैंडिंग नेटवर्क जो इसे रेस्टोरेबल मुद्दों से रहित डाटा और ध्वनि ट्रैफिक को निर्बाध रूप से वहन करने में समर्थ बनाते हैं, के स्वामित्व हित/क्षमता/अलोप्य प्रयोगाधिकार हैं। चेन्नई से सिंगापुर की अपनी केबल प्रणाली के अतिरिक्त, वीएसएनएल के पास भारत में बिछाए कई मुख्य परिचालनिक समुद्रतलीय आप्टिक फाइबर केबल नेटवर्कों का स्वामित्व है। टेलीजियोग्राफी (अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ अनुसंधान एजेंसी) जिसमे वर्ष 2004 में भारतीय बैंडविड्थ मूल्यों के कवरेज की शुरूआत की थी, ने अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ 2005 पर अपनी रिपोर्ट (प्राइमट्रिका इंक. अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ रिपोर्ट, 2005) में यह उल्लेख किया है कि **'भारतीय ऑफ सर्किटों के लिए 85% राजस्व वीएसएनएल द्वारा अर्जित किया गया है'**। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल्य निर्धारण सामान्यतः दो अलग हॉफ सर्किट मूल्यों के आधार पर किया गया है : पहला भारती कंपनी वीएसएनएल की ओर से तथा दूसरा एक विदेशी वाहक की ओर से। इससे यह सिद्ध होता है कि वीएसएनएल का यह तर्क कि आईपीएलसी बाजार में इसके बड़े 'प्रतिस्पर्धी' हैं, तथ्यों पर आधारित नहीं है।

28. इसी तर्क को कुछ आगे बढ़ाते हुए, वीएसएनएल ने 'दूरसंचार में प्रतिस्पर्धा नीति' पर पृष्ठभूमि पत्र (नवम्बर, 2002) से यह उद्धृत किया है कि मात्रात्मकता और गुणात्मकता की दृष्टि से ऐसे कई घटक हैं जिनको यह निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाना होता है कि **बाजार में हमारा प्रभुत्व स्थापित** हो चुका है या नहीं।

29. प्राधिकरण इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी को इस दृष्टि से सीमित रखेगा कि वीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत की गई इसी रिपोर्ट में भी पैरा 3.13 में यह उल्लेख है कि **"यद्यपि इन कारकों का सापेक्ष महत्व मुख्यतः मामला–दर–मामला आधार पर निर्धारित किया जाता है, तथापि प्रभुत्व निर्धारित करने के लिए बाजार हिस्सेदारी सामान्यतः प्रारंभिक**

बिंदु के रूप में प्रयोग की जाती है। सामान्यतः, बाजार में 40% से 50% की हिस्सेदारी प्रभुत्व की उच्चा का द्योतक है।" वीएसएनएल की अपनी स्वीकृति के अनुसार, बाजार में इसकी 60% की हिस्सेदारी है।

30. वीएसएनएल ने यह तर्क दिया है कि वास्तव में वह एक अकेला ऑपरेटर है और यह अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ तथा अपने **परिचालन के दूसरे सेगमेंट में एक्सेस प्रदाताओं पर निर्भर है।**

31. प्राधिकरण ने वार्षिक रिपोर्ट 2003–04 में समाविष्ट कतिपय तथ्यों पर आधारित वीएसएनएल के उक्त विवरण की जांच की और इन्हें यहां पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है :–

- 237 अन्तरराष्ट्रीय गंतव्यों को टेलीफोन सेवा मुहैया कराने वाली वीएसएनएल अभी भी भारत की उच्च अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा प्रदाता कंपनी है।
- सितम्बर, 2002 में, वीएसएनएल ने एनएलडी सेवा बाजार में प्रवेश किया।
- वीएसएनएल इंटरनेट एक्सेस और इंटरनेट टेलीफोनी जैसी इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने वाली अग्रणी कंपनी है और मुख्य रूप से फुटकर ब्राडबैंड व्यवसाय को बढ़ाने की योजना बना रही है।

- वर्ष 2003–04 के दौरान वीएसएनएल का पट्टे पर दी गई लाइनों का व्यवसाय 83% बढ़ा और कंपनी को इस व्यवसाय के इसी प्रकार बढ़ने की उम्मीद है।

- नवम्बर, 2002 में, वीएसएनएल भारत की पहली वीपीएन विक्रेता कंपनी बनी।

- 31 मार्च, 2002 की टीटीएसएल इक्विटी में वीएसएनल की कुल निवेश 6 बिलियन रुपए रहा जो देश भर में ग्राहकों को भारी मात्रा में एक्सेस मुहैया कराएगा।

32. वीएसएनएल की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ट–7 में इस प्रकार उल्लेख किया गया है :– ”12 बिलियन अमेरिकी डालर वाले टाटा समूह का अंश होने के नाते वीएसएनएल को बहुत लाभ होता है तथा यह ग्राहकों को सभी सुविधाओं की विस्तृत रेंज मुहैया कराने के लिए दूरसंचार और सॉफ्टवेयर सेक्टर में कार्यरत टाटा समूह की अन्य कंपनियों के साथ सहक्रियाओं का भरूपर उपयोग कर रही है।“

33. अतः उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के रूप में टाटा की अन्य समूह कंपनियों के सहयोग से वीएसएनएल का परिचालन ऊर्ध्वस्थ एकीकृत सेवा व्यवस्था की प्रकृति का है न कि “एक अकेले ऑपरेटर” की प्रकृति का।

34. वीएसएनएल ने दावा किया है कि पिछले तीन वर्षों के उसके एकाधिकार के छिन जाने से उसकी वित्तीय निष्पादन स्थिति बिगड़ती जा रही है। प्राधिकरण का मत है कि आईपीएलसी को टैरिफ विनियमन की आवश्यकता है क्योंकि मार्किट में प्रतिस्पर्धा की कमी है। अतः इसे वीएसएनएल की वित्तीय निष्पादन की स्थिति से नहीं जोड़ा जा सकता, जो कि बहुत से कारकों पर निर्भर है। इसके अलावा, मारगन स्टेनले द्वारा अप्रैल, 2005 में वीएसएनएल पर उनकी निवेश समीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वीएसएनएल का डाटा व्यवसाय बढ़ेगा और यह 2005 के 3.7 बिलियन से बढ़कर 2007 में 8 बिलियन हो जाएगा। जिससे कंपनी के कुल ईबीआई टीडीए में उसका अंशदान 54% से बढ़कर 73% हो जाएगा और उन्हें वीएसएनएल के डाटा व्यवसाय से परिचालनिक मार्जिन के आईएलडी टेलीफोनी व्यवसाय के 6% परिचालनिक मार्जिन के संबंध में 43–45% तक बढ़ने की उम्मीद है (स्रोतः जे. एम. मोरगन स्टैनले, इक्विटी रिसर्च, एशिया पैसेफिक की विदेश संचार निगम के संबंध में 5 अप्रैल, 2005 की रिपोर्ट)। वास्तव में आईपीएलसी टैरिफ में कमी से अंतिम उपायेगकर्त्ता द्वारा अधिक क्षमता की मांग को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे सेवाओं के लिए उपलब्ध क्षमता में वृद्धि होगी और इस तरह वीएसएनएल की समग्र लागत में कमी आएगी। अतः वीएसएनएल मात्र इस आधार पर टैरिफ विनियमन का विरोध नहीं कर सकता कि इससे उसका गैर–आईपीएलसी व्यवसाय कम–लाभप्रद हो जाएगा।

35. प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रत्युत्तर में वीएसएनएल ने अन्य टेलीकॉम ऑपरेटरों से उसके संबंधों और केबल क्षमता आदि से उसके संपर्क से संबंधित मुद्दे पर कुछ टिप्पणियां की हैं। चूंकि प्राधिकरण ने भारत में अन्तरराष्ट्रीय निजी लीज सर्किटों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले उपायों पर एक अलग से परामर्श–पत्र (संख्या 5/2005) जारी किया है, इसलिए प्राधिकरण को आईपीएलसी में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की दृष्टि से अपनी विनियमन नीति का गठन करते समय विचार करना होगा और इन्हें उचित तरीके से प्रस्तुत करना होगा।

बहुत से देशों में आईपीएलसी विनियमन के साक्ष्य

36. प्राधिकरण ने बहुत से देशों में आईपीएलसी मार्किट को शासित करने वाले विनियम की अन्तरराष्ट्रीय पद्धतियों की एक विस्तृत समीक्षा की है। समीक्षा के परिणाम तालिका में दिए गए हैं और बहुत से देशों में आईपीएलसी क्षेत्र को शासित करने वाली विनियमन पद्धति का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक 'क' के परिशिष्ट 5** में दिया गया है। उस समीक्षा के अनुसार बहुत सी मार्किट जिन्हें आज प्रतिस्पर्धी मार्किट समझा जाता है, वहां किसी न किसी समय टैरिफ विनियमन सहित विभिन्न प्रकार के विनियमन लागू किया गया था। आज भी आईपीएलसी के लिए कुछ प्रतिस्पर्धी मार्किटों में प्रभुत्व वाले ऑपरेटरों को टैरिफ विनियमन का पालन करना पड़ता है, जिसमें उन्हें अपने टैरिफ विनियामक के समक्ष दायर करने पड़ते हैं, जिनकी बाद में सूक्ष्म जांच की जाती है और पूर्व अनुमोदन लिया जाना आवश्यक होता है, जो कि तभी दिया जाता है जबकि विनियामक प्रस्तावित दरों से पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। इन्कमबेंट द्वारा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रत्युत्तरों से यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि वियतनाम, सिंगापुर और ताइवान जैसे देशों में आईपीएलसी क्षेत्र का विनियमन होता है। वियतनाम के मामले में यह दर बैंड/अधिकतम सीमा और विनियामक के पूर्व अनुमोदन के रूप में होता है। ताइवन के मामले में आईपीएलसी में प्रभुत्व वाले ऑपरेटर के लिए विनियमन की किस्म दर बैंड और अधिकतम सीमा के रूप में होती है। सिंगापुर में प्रभुत्व वाले आईपीएलसी ऑपरेटरों के, टैरिफ के लिए विनियामक से पूर्व अनुमोदन लेना पड़ता है। **प्रत्येक**

देश को यह निर्णय लेना पड़ता है कि एक विशेष मार्किट का विनियमन किया जाए अथवा नहीं, और भारत आईपीएलसी के विनियमन के लिए एक उचित मार्किट है।

37. अतः आईपीएलसी के लिए टैरिफ विनियमन की आवश्यकता के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया निष्कर्ष उद्‌देशीय कारकों और विभिन्न अंशधारकों के प्रत्युत्तरों सहित संबद्ध डाटा की जांच पर आधारित है।

हाल की गतिविधियां

38. वीएसएनएल ने अपने उत्तर में हाल ही के कुछ कार्यकलापों का उल्लेख किया और उसने यह तर्क दिया कि भारत में अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्‌थ मार्केट के कार्यकलापों के दृष्टिगत आईपीएलसी मूल्यों के विनियमन का कोई औचित्य नहीं है। इनकी चर्चा नीचे की जा रही है :

"नई क्षमताओं और प्रतिस्पर्धा की प्रत्याशा में मूल्यों में कमी करना"

39. प्राधिकरण ने हर्ष के साथ नोट किया कि वीएसएनएल द्वारा (15 अगस्त, 2005 से लागू) दो मार्गों एक चेन्नई–सिंगापुर और दूसरा चेन्नई–यूएसए (पैसेफिक भाग) पर आईपीएलसी टैरिफ में हाल में कमी की गई है। बहरहाल, ऐसी कमी भारत को यूरोप और यूएसए (पूर्व तट) से जोड़ने वाले एटलांटिक महासागर के अधिक महत्वपूर्ण मार्ग और इन्ट्रा–एशिया पैसीफिक (सिंगापुर के अलावा) के गंतव्यों के संबंध में नहीं की गई। इसके अलावा वीएसएनएल के अलावा अन्य आईपीएलसी प्रदाताओं ने इसके परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी नहीं की है। अतः यह समान रूप से आवश्यक है कि सभी गंतव्यों, सभी मार्गों तथा सभी क्षमताओं में और सभी ऑपरेटरों के लिए आईपीएलसी मूल्यों में कमी की जाए। इस आदेश के तहत प्राधिकरण द्वारा अधिदेशित टैरिफ विनियम में अधिकतम टैरिफ की व्यवस्था की गई है और इस सीमा तक सभी ऑपरेटरों के लिए प्राइस–बैंड को अधिकतम सीमा में रखने हेतु पर्याप्त लोचशीलता है।

"भारती का आई 2 आई केबल अब रेस्टोरेबल सेवाएं उपलब्ध कर सकती हैं"

40. प्राधिकरण ने नोट किया कि हाल–फिलहाल में वीएसएनएल और नेटवर्क आई 2 आई के बीच परस्पर रेस्टोरबल करार भी एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि ऐसे करार में ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि की संभाव्यता होती है। इससे निकट भविष्य में आईपीएलसी मार्किट में प्रतिस्पर्धा की स्थिति में अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि अब भारत–सिंगापुर मार्ग पर एक और ऑपरेटर के पास रेस्टोरेबल क्षमता है। परन्तु समग्र टैरिफ के आकलन से यह स्वतंत्र है क्योंकि इससे होने वाली संभावित प्रतिस्पर्धा से मार्किट के एक सीमित भाग अर्थात् सिंगापुर को अथवा उससे होकर गुजरने वाले मार्गों पर ही प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर सभी अन्य मार्गों और गन्तव्यों पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

"रिलायंस इन्फोकॉम फालकन नामक सबमेरीन केबल प्रणाली भी बिछा रहा है........ बीएसएनएल अपनी स्वतंत्र केबल लैंडिंग स्टेशनों और बहु–केबल प्रणालियों के निर्माण की योजना बना रहा है"

41. प्राधिकरण के मत में ये कार्य जब कभी भी पूरे होंगे तब ये आईपीएलसी मार्किट के लिए महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि इनसे मार्किट में और अधिक प्रतिस्पर्धा आने की संभावना है। इन संकेतों से वैश्विक संदर्भ में भारत में डाटा सेवा मार्किट की महत्ता का भी पता चलता है और यह भी पता चलता है कि भारत में प्रमुख आईएलडीओ के निवेश के ऐसे निर्णय भारत में अन्तरराष्ट्रीय सेवाओं की वृद्धि के बारे में किए गए आकलनों के अनुरूप हैं। प्राधिकरण का मत है कि इस मार्किट में मौजूदा और कुछ समय पहले के रूझानों के आधार पर आईपीएलसी सेवाओं के विनियमन की आवश्यकता अथवा अन्यथा का आकलन करना होगा। संभावित/प्रत्याशित विकास, जब वे वास्तव में प्राप्त हो जाते हैं और मार्किट पर प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावशाली हो जाते हैं तब से वर्तमान परिदृश्य को ठीक करने के लिए निर्णयों की समीक्षा के लिए आवश्यक अवसर मुहैया कराते हैं।

भारतीय आईपीएलसी मार्किट की विनियमन की आवश्यकता है।

42. इस तथ्य के दृष्टिगत कि दुनिया के दूसरे भागों की तुलना में और विषम मार्किट परिस्थितयों के कारण सेवाओं के प्रावधानों की लागत की तुलना में भारत में आईपीएलसी टैरिफ में काफी समय से ज्यादा कमी नहीं आई है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आईपीएलसी की सेवाएं ब्राडबैंड/इन्टरनेट सेवाओं और आईटी एवं आईटी आधारित सेवाओं की पैठ के लिए महत्वपूर्ण हैं, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वर्तमान में आईपीएलसी के लिए अधिकतम टैरिफ निर्धारित करना आवश्यक है। इस उपाय से उद्योग में समान अवसर के वातावरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

खण्ड – III

लागत आधारित टैरिफ के आकलन के लिए उपयोग की गई पद्धति से संबंधित मुद्दों के बारे में वीएसएनएल की टिप्पणी और उस पर प्रतिक्रिया।

43. वीएसएनएल ने दावा किया है कि औसत भारित मूल्य के आधार पर अधिकतम टैरिफ निर्धारित करना उचित नहीं है क्योंकि दूरी और लागत में 'परफेक्ट कोरिलेशन' (पूर्ण सम्बद्धता है) है। प्राधिकरण समझता है कि वीएसएनएल का यह तर्क इस मुद्दे के तथ्यों के अनुसार सही नहीं है, जैसे की नीचे चर्चा की गई है :

दूरी और कीमत में पूर्ण सम्बद्धता नहीं है

44. सबमेरीन केबल प्रणाली की लागत दूरी का एक रेखीय कार्य नहीं है। वास्तव में सबमेरीन केबल प्रणाली के उच्च्च डिजाइन क्षमता के कारण यूनिट क्षमता लागत पर पर्याप्त प्रभाव डालने के लिए लंबे केबलों से संबद्ध अतिरिक्त लागत पर्याप्त नहीं है। एक केबल

प्रणाली की उच्च क्षमता की योग्ताओं का अर्थ होगा अतिरिक्त केबल/रिपीटरों से संबद्ध अलग–अलग इकाई क्षमता लागत में कमी होना। इसके अलावा प्रौद्योगिकीय प्रगति से केबल प्रणाली के लिए आवश्यक एम्पलीफायर/रिपीटरों की संख्या में कमी आई है, जिससे केबल प्रणाली की समग्र लागत में भी कमी आई है।

45. यह ज्ञात तथ्य है कि अन्तरराष्ट्रीय ऑपरेटरों की सबमेरीन क्षमता (कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में) की लागत में तेजी से कमी हो रही है और अक्सर इसे इस प्रकार से पैकेज किया जाता है कि यह दूरी पर निर्भर नहीं होती । भारत में आईएलडीओ के लिए प्रभारित आईपीएलसी के टैरिफ से इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस स्थिति को टेलीजियोग्राफी में भली–भांति उल्लिखित किया गया है जिसे नीचे निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

टैरिफ दूरी पर निर्भर नहीं होती

रूट/गंतव्य	Q2.2004	Q3.2004	Q4.2004
लंदन–मुंबई	$10,605	$8,156	$9,638
हांग–कांग–मुंबई	$8,174	$7,450	$7,611
मुंबई–सिंगापुर	$8,174	$7,519	$8,065
लास एंजेलिस–मुंबई	$8,636	$7,301	$9,003
मुंबई–न्यूयार्क	$8,869	$7,061	$8,614

टिप्पणी : मूल्य औसत ई–1 मासिक सूचीबद्ध मूल्य दर्शाते हैं, जिसमें इंस्टालेशन फीस शामिल नहीं है। मूल्य दो हॉफ सर्किटों के मिश्रित मूल्य दर्शाते हैं।

स्रोत : टेलीजियोग्राफी अनुसंधान (प्रिमेट्रिका इन्क 2005, इंटरनेशनल बैंडविड्थ, 2005)

46. नवम्बर, 2004 में (बीसीजी रिपोर्ट) वीएसएनएल ने मूल्य संरचना के संबंध में अपनी प्रस्तुति में मात्र एक औसत मूल्य को दर्शाया था न कि दूरी आधारित मूल्य माडल को।

47. यहां यह समझना आवश्यक होगा कि वीएसएनएल द्वारा उपगत सभी आवश्यक लागतों को प्राधिकरण ने अधिकतम मूल्य के निर्धारण के समय ध्यान में रखा है। वास्तव में कंसोरटियम केबल प्रणालियों में वीएसएनएल के निवेश के एक बड़े हिस्से की वसूली पहले ही की जा चुकी है, जैसा कि 30 अप्रैल, 2004 के परामर्श पत्र सं. 10/2004 (पैरा 17–20) में उल्लेख किया गया है।

48. इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा ऐसे निर्धारित अधिकतम मूल्य में काफी बफर मौजूद हैं। चूंकि प्राधिकरण के अधिदेश द्वारा प्राप्त टैरिफ एक अधिकतम टैरिफ होती है, इसलिए यह सर्विस प्रोवाइडरों को विभिन्न गंतव्यों/मार्गों आदि के लिए भिन्न–भिन्न टैरिफ के प्रस्ताव करने की आजादी देता है, बशर्ते कि ऐसी टैरिफ अधिकतम टैरिफ से अधिक न हों और पारदर्शी प्रकृति के हों। नई केबल प्रणाली के अधिग्रहण और सिंगापुर के लिए पूर्ण निजी स्वामित्व वाली केबल प्रणाली की स्थापना से विभिन्न गंतव्यों के लिए आईपीएलसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वीएसएनल का भारित औसत मूल्य काफी कम आएगा और इससे वीएसएनएल के पास पर्याप्त बफर उपलब्ध रहेगा। प्राधिकरण के समक्ष हाल ही में वीएसएनएल द्वारा दायर किए गए टैरिफ से यह बात सिद्ध होती है कि आईपीएलसी कर कीमतें सीधे दूरी से संबद्ध नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए चेन्नई से यूएसए के लिए प्रति ई–1 प्रति वर्ष दर 11 लाख रुपए और चेन्नई से सिंगापुर प्रति ई–1 प्रति वर्ष 10 लाख रुपए है।

49. अन्त में, संपूर्ण सबमेरीन से संबद्ध लागत अथवा एक केबल प्रणाली में वेट तत्व डूबी लागत जैसी है। अतः लंबी दूरी के केबलों के उन्नयन करते समय कोई इंक्रीमेंटल वेट सेगमेंट लागत उपगत नहीं होती है। लंबी दूरी के केबलों के ऐसे उन्नयन से संबद्ध लागत मात्र ड्राई एंड लागत है जो दूरी से अलग होती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि एसईए–एमई–डब्ल्यू ई–3, एसएएफई और एसईए–एमई–डब्ल्यू ई–4 आदि जैसी केबल प्रणालियां, कंसोरटियम

केबल प्रणालियों की पूरी लंबाई के निर्माण की पूरी लागत वहन नहीं करती है। बल्कि इसमें कंसोर्टियम के सदस्यों की हिस्सेदारी होती है। ऐसे कंसोरटियम केबलों में क्षमता की खरीद की पद्धति न्यूनतम निवेश इकाई (एमआईयू) कि.मी. की प्रणाली हो सकती है। इन एमआईयू कि.मी. के एक पूल को प्रत्येक लैंडिंग पार्टी/आंशिक स्वामी के लिए लगाया जाता है और दूरस्थ आधी दूरी के लिए क्षमताओं/मार्गों का पार्टी के साथ भागीदारी से "स्पैन्डिग" एम आई यू कि.मी. के बदले में "खरीदा" जाता है। हालांकि एम आई यू कि.मी. की खरीद की संकल्पना इन केबलों पर विद्यमान है, परन्तु प्रत्येक मार्ग के साथ संबद्ध एमआईयू कि.मी. सीधे दूरी से संबद्ध नहीं होती है।

50. उक्त के दृष्टिगत, दूरी और लागतों के बीच ऐसा कोई 'पूर्ण–संबंध' नहीं होता जैसाकि वीएसएनएल का दावा है और अतः यह अधिकतम टैरिफ के निर्धारण के लिए औसत मूल्य के उपयोग का कोई कारण नहीं है।

<u>वीएसएनएल द्वारा आरबिट्रेज अवसर को बहुत अधिक दर्शाया गया है</u>

51. वीएसएनएल ने यह भी उल्लेख किया है कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आईपीएलसी के लिए टैरिफ संरचना अर्थात डीएस–3 और एस टी एम–1 के लिए ई–1 के 8 गुणा और 23 गुणा प्राइस मल्टिपल सहित, 13 लाख रुपए प्रति ई–1, से आरविटरेज का अवसर सृजित होगा जिससे इसके प्रतिस्पर्धी वीएसएनएल से एसटीएम–1 खरीदेंगे और उसे लागत से कम पर ई–1 स्तर पर ग्राहकों को फायदे पर बेच देंगे। प्राधिकरण द्वारा इस बात पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया और यह देखा गया कि इस संबंध में वीएसएनएल की आशंकाएं निम्नलिखित कारणों से अनुचित हैं :–

52. आरबिटरेज अवसर वह है, जिसे बहुत से बाजारों में दोहराया जाता है और इसका वीएसएनएल द्वारा अधिकथन किया गया है। इस मामले के लिए आईपीएलसी के लिए वहां विद्यमान वीएसएनएल के मौजूदा टैरिफ संरचना में भी आरबिट्रेज अवसर उपलब्ध है। लेकिन

यह एक विषम स्थिति का अत्यधिक सरलीकरण है जिसमें पुनर्बिक्री, वह भी अन्य आईएलडीओ द्वारा बिक्री शामिल है। एसटीएम–1 क्षमता की खरीद के बाद ई–1 की पुनर्बिक्री में 63, ई–1, ग्राहकों का होना जरूरी है, जिसमें पर्याप्त लागत और समय लगेगा। इसके लिए आगे एक एनएलडी आपरेटर और ग्राहकों को सीधे इस क्षमता को बेचने के लिए एक बीएसओ/यूएएस लाइसेंस की सुविधाओं की आवश्यकता होगी। इसके आगे, एक आपरेटर से एसटीएम–1 क्षमता तकनीकी रूप से लेकर उसके मार्किट में ई–1 क्षमता के रूप में पुनर्बिक्री की कोशिश के लिए उपकरण और आईटी अवसंरचना की आवश्यकता होगी। इसके अलावा वीएसएनएल जैसे एसटीएम–1 के विक्रेताओं से संबंधित लाभ में ग्राहकों को एक बड़े वित्त पोषण की वचनबद्धता, एक सरल बिक्री और सेवा प्रक्रिया भी विद्यमान रहेगी और इससे सामान्यतः कम प्रशासनिक लागत और क्षमता की बेहतर उपयोगिता होगी और परिणामतः इसमें क्षमता से कम लागत आएगी।

<u>मूल्य गुणक और उसके आर्थिक मूलाधार</u>

53. प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया मूल्य अनुपात एकक और वीएसएनएल की आपत्तियां इस मुद्दे से निकट संबद्ध है। जब माल/सेवाओं के थोक व्यापार से ही बड़े पैमाने पर मितव्ययता आएगी। यह आईपीएलसी सेवाओं के लिए भी लागू है। एसटीएम–1, डीएस–3 से बड़ी क्षमता है और डीएस–3 ई–1 से भी बड़ी क्षमता है। यहां पर विचार की जा रही तीन क्षमताओं की वास्तविक क्षमता अनुमान 1:21:63 है। तीन क्षमताओं अर्थात् ई–1, डीएस–3 और एसटीएम–1 के लिए मूल्य अनुपात परिचालन में स्केल की मितव्ययता के कारण इसी अनुपात में नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि उदाहरण के लिए एसटीएम–1 का मूल्य डीएस–3 के मूल्य के तीन गुणा कम होगा। जब बड़ी क्षमताएं खरीदी जाती हैं तो मूल्य कम होते हैं क्योंकि बड़ी क्षमताओं को बेचने की लागत भी छोटी क्षमताओं को बेचने की लागत की तुलना में कम होती है। मूल्य गुणांक के पीछे आर्थिक औचित्य को **"अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ–सबमेरीन नेटवर्क, पर हाल की अन्तरराष्ट्रीय रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया है। इसमें कहा गया है कि :–**

"क्षमता–मूल्य गुणांक"

बैंडविड्थ बहुत सी वस्तुओं के समान बड़ी मात्रा में खरीदने पर प्रति इकाई के आधार पर सस्ती पड़ती है। उदाहरण के लिए, डीएस–3 सर्किट, जिनमें कि ई–1 सर्किटों से 22 गुणा अधिक क्षमता होती है, आमतौर पर ई–1 से सिर्फ चार से आठ गुणा अधिक मूल्य के होते हैं। कैरियर प्रभार अनुपातिक आधार पर छोटे सर्किटों के लिए अधिक प्रभार वसूलते हैं क्योंकि बिट–दर–बिट आधार पर विक्रेता को छोटी क्षमताओं के रखरखाव के लिए बड़ी क्षमता से अधिक खर्च करना पड़ता है। बिक्री, विधि फीस, संस्थापनाएं और कुछ अनुरक्षण लागतें सहित कुछ व्यवस्था लागतें सर्किट के आकार पर निर्भर न होकर निर्धारित होती हैं।

परम्परागत रूप से विभिन्न क्षमताओं के मूल्य उचित रूप से अनुमानित मल्टीपल्स में आते थे। डीएस–3 से एसटीएम–16 में प्रत्येक उत्तरोत्तर सर्किट वृद्धि पर आमतौर पर मूल्य दो गुणा हो जाती है, जबकि क्षमता कभी–कभी चार गुणा हो जाती है। बहरहाल, हाल के वर्षों में बड़ी मात्रा में खरीद पर छूट का प्रचलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि ऑपरेटर बढ़ते हुए वित्तीय दबाव के बीच काम करते हैं। चूंकि उच्च क्षमता के सर्किटों के मूल्य छोटे क्षमता के सर्किटों के मूल्यों से ज्यादा तेजी से कम हो रहे हैं, इसलिए क्षमता मूल्य गुणांक बड़ी तेजी से घटा है। परिणामस्वरूप एक एसटीएम–1, एक ई–1 से 76 गुणा ज्यादा डाटा वहन कर सकता है परन्तु इसे एक ई–1 के मूल्य से तीन से 15 गुणा ज्यादा पर पट्टे पर दिया जा सकता है।"

(स्रोतः प्रिमेटरिका इन्क, अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ रिपोर्ट 2004–प्रिमेटरिका इन्क)

54. ऊपर दिए गए साक्ष्यों का आशय है :

क) मूल्य अनुपात संबंधित क्षमताओं के अनुपात से कम होना चाहिए।

ख) आईपीएलसी के लिए भारतीय बाजार से प्राप्त मूल्य, विश्व में विद्यमान मूल्य अनुपात ई–1, डीएस–3 और एसटीएम–1 के लिए क्षमता गुणांक अनुपातों से काफी कम हैं।

(ग) अन्तरराष्ट्रीय रूप से विद्यमान अधिकतम मूल्य अनुपात जिनकी रिपोर्ट की गई है वह डीएस–3 के लिए ई–1 के मूल्य से 8 गुणा के बराबर और एसटीएम–1 के लिए ई–1 के मूल्य के 15 गुणा के बराबर है।

(घ) अतः, यदि कोई इससे ही अंदाजा लगाए तो ई–1, डीएस–3 और एसटीएम–1 के संबंध में अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ के मूल्य अनुपात अधिकतम 1:8:15 होना चाहिए।

55. इस विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मूल्य अनुपात अर्थात् 1:8:23 विश्व में अन्यत्र विद्यमान से कहीं अधिक है। और अधिक महत्व की बात यह है, कि भारित औसत के आधार पर (इन गुणाकों पर) वीएसएनएल के लिए राजस्व वसूली से वीएसएनएल की लागत वसूल हो जाएगी और साथ ही अधिदेश भी बच जाएगा। इससे ट्राई द्वारा टीडीसैट को दिए गए अधिदेश के संबंध में वीएसएनएल को सूचित कर दिया गया है। **(ब्यौरे के लिए अनुबंध का परिशिष्ट 4 देखें)** भारत में आईएलडीओ द्वारा प्रस्तावित विद्यमान टैरिफ ने इन क्षमताओं, के लिए अनुपात दिए गए हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय मूल्य अनुपात (नीचे तालिका देखें) की तुलना में काफी अधिक थे।

आईपीएलसी मूल्य की अंतरराष्ट्रीय तुलना (ई–1 मूल्य और मूल्य गुणांक)

देश	ई–1 मूल्य, यूएस डालर'000	डीएस–3 मूल्य यूएस डालर' मिलियन	एसटीएम–1 मूल्य यूएस डालर' मिलियन	कालमों का अनुपात (1):(2):(3)
जपान	23	0.10	0.2	1:4:8
दक्षिण कोरिया	23	0.10	0.2	1:4:8
हांग–कांग	24	0.12	0.3	1:5:11
सिंगापुर*	33	0.17	0.3	1:5:11
भारत**	**41**	**0.70**	**1.8**	**1:17:44**

अन्तरराष्ट्रीय आंकड़ों के स्रोत : अरनेस्ट एण्ड यंग / टेलीजियोग्राफी

नोट : यूएस डालर = 44 रुपए

* सिंगापुर के ई–1 मूल्य अन्य बातों के साथ–साथ डीएस–3 और एसटीएम–1 के लिए कम गुणकों के कारण अधिक हैं।

** भारत–यूएसए के लिए (ऐटलान्टिक मार्ग) के लिए जून, 2005 से प्रस्तावित वीएसएनएल के आईपीएलसी हॉफ सर्किट टैरिफ

मूल्यों के मामले में वीएसएनएल पर कंसोरटियम द्वारा लगाए गए दबाव का कोई साक्ष्य नहीं है।

56. वीएसएनएल ने मूल्य अनुपात का विरोध इस आधार पर किया है कि भारत से बाहर बेची जाने वाली अधिकतर सबमेरीन केबल क्षमताएं कंसोरटियम केबल पर होती है। प्राधिकरण ने नोट किया कि इस तर्क का कोई आधार नहीं है क्योंकि कंसोरटियम के सदस्य मूल्यों को निर्धारित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते और वीएसएनएल ने प्राधिकरण के समक्ष

वीएसएनएल पर कंसोरटियम द्वारा मूल्यों के मामले में कोई दवाब होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

57. इसके अलावा, इन अनुपातों को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा से ऊपर उठाने से वीएसएनएल को अदेय अधिशेष प्राप्त होगा, जिसका विभिन्न क्षमताओं के लिए भारित औसत के आधार पर पूर्ण लागत वसूली के आधार पर और कुल में इन प्रत्येक क्षमताओं के हिस्से से प्राधिकरण ने सत्यापन किया है। एक बार ई–1 के मूल्य निर्धारण से वीएसएनएल द्वारा पूर्ण लागत वसूली सुनिश्चित हो जाने के बाद है और अन्य उच्च क्षमताओं के लिए मूल्य अनुपात के आधार पर राजस्व वसूली के कम होने का प्रश्न नहीं उठता।

आकलन में उपयोग किए गए मिश्रित क्षमता का अनुमान

58. वीएसएनएल ने कहा है कि टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में उपयोग किए गए क्षमता मिश्रित अनुपात "अनुचित" हैं। वीएसएनएल को उपलब्ध कराई गई (खुलासे के हिस्से के रूप में) आकलन शीट जिनमें लागतों का विस्तृत आकलन शामिल है, यह उचित रूप से प्रदर्शित किया गया है कि यदि डीएस–3 और एसटीएम–1 के संबंध में कुल क्षमता का 50% भी बेचा जाता है तो वीएसएनएल का राजस्व पर्याप्त से अधिक होगा। यदि यह भी माना जाता है कि वीएसएनएल द्वारा परिकल्पित अधिक क्षमता भविष्य में एसटीएम–1 जैसी उच्च क्षमताओं के संबंध बड़ी क्षमताएं बेची जा सकती हैं, तो यह भी तथ्य–परक होगा कि ई–1 की तुलना मे एसटीएम–1 को बेचने से स्केल मितव्ययता में पर्याप्त कमी भी आएगी। क्षमता मिश्रित अनुमानों की रेंज के प्रयोग की प्रक्रिया से पता चलता है कि राजस्व की भारित औसत वसूली अधिशेष को छोड़ते हुए भी औसत लागत से अभी भी अधिक होगी (वीएसएनएल को सूचित लागत अनुमान में प्रदर्शित)। इसके अलावा, एक दी गई समयावधि में यदि निम्न क्षमता से उच्च क्षमता जैसे एसटीएम–1 (एक बड़े आकार वाले) में ग्राहकों का स्थानांतरण होता है तो यह

तभी हो सकता है जबकि बेची गई कुल क्षमता भी साथ–साथ बढ़े हैं और स्थिति में प्रति क्षमता यूनिट लागत, सेवाओं में क्षमता के उच्च उपयोग के कारण कम हो जाएगी।

वीएसएनएल द्वारा उठाए गए लागत डाआ और लागत के आकलन से संबंधित मुद्दे और उनपर टिप्पणियां

59. वीएसएनएल द्वारा लागत प्रक्रिया पर उठाया गया एक और मुद्दा यह है कि प्राधिकरण द्वारा लागत का कम अनुमान लगाया गया है। वीएसएनएल के प्रति ई–1 की उच्चतर लागत के दावे की विस्तृत जांच इस खण्ड के विभिन्न पैराग्राफों में की गई है। इसके अलावा, वीएसएनएल ने दावा किया है कि कुछ अतिरिक्त निवेश/परिचालनिक व्यय उनकी नई केबल प्रणाली में हुए/किए गए हैं, ये सभी आईपीएलसी सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रभावी लागत में काफी प्रभाव डालेंगे और अतः लागत की जांच के लिए नए सिरे से एक नई प्रक्रिया आवश्यक है। इसका निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

सबमैरिन केबल बिल्डिंग की कीमत में गिरावट

60 नए केबल की लागत के संबंध में वीएसएनएल का मत सही नहीं है और वास्तव में प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जा रहे पुरानी लागत की तुलना में यह कम लागत प्रदान करता है। मोरगन स्टैनले द्वारा अप्रैल, 2005 की अपनी रिपोर्ट में दिए गए सबमैरिन केबल प्रणाली, (नीचे तालिका देखें), की लागत तुलना यह दर्शाती है कि सबमैरिन केबल बिल्डिंग की लागत में तेजी से गिरावट हो रही है :–

सबमैरिन केबल बिल्डिंग की लागत में गिरावट हो रही है

केबल प्रणाली	अभिकल्प क्षमता		लंबाई	लागत
	आर एपफ एस	(जी बी पीएस)	(0'000 कि.मी.)	अमेरिकन डालर
टी जी एन			60.00	3,246*
ट्राँस पैसिफिक	2002	7,680		
ट्राँस अटलांटिक	2001	2,560		
प. यूरोप		3,840		
नार्थन यूरोप रिंग		640		
फलैग				3,150*
अटलांटिक 1	2001	2,400	14.5	
यूरोप–एशिया	1997	80	28.0	
नार्थ–एशिया लूप	2002	2,880	9.5	
आई–2–आई	2002	8,400	3.2	650
एसईए–एमई–डब्ल्यूई–2	1994	1,100	18.0	800
एसईए–एमई–डब्ल्यूई–3	1999	505	38.0	1,500
एसईए–एमई–डब्ल्यूई–4	2005	1,000	20.0	500
टाटा इंडिकॉम केबल	2004	5,120	3.2	100

* मोरगन स्टैनले अनुसंधान अनुमान

स्रोत : जेएम मोरगन स्टैनले, इक्यूटी रिसर्च, एशिया पैसिफिक, विदेश संचार निगम लिमिटेड पर रिपोर्ट, 5 अप्रैल, 2005

आरएफएस : सेवा के लिए तैयार है.

61. इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा नए केबल प्रणाली, आईएलडीओ द्वारा केबल प्रणाली के अधिग्रहण में निवेश पर आधारित टैरिफ के निर्धारण का तरीका नहीं अपनाया है जिसका अर्थ है निर्धारित लागत की तुलना में इसकी काफी कम कीमत होगी। फिर भी टैरिफ विनियमन के लिए बाद की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस आदेश के तहत निर्धारित आईपीएलसी टैरिफ की समीक्षा करने की आवश्यकता पड़ी तो प्राधिकरण इसकी समीक्षा करेगा।

लागत की गणना के बफर – एफएलएलआरआईसी का उपयोग नहीं किया गया है

62. वीएसएनएल ने अपनी प्रस्तुतीकरण में कहा (बिना किसी आधार के) है कि लागत आकलनों में दर्शाए गया बफर सही नहीं है। यही सभी स्वीकार करते हैं कि एफएलएलआरआईसी मूल्य निर्धारण की ऐसी विधि है जो सेवा प्रदताओं को कुशल बनने के लिए बाध्य करती है। बहरहाल, प्राधिकरण ने इस समय एफएलएलआरआईसी का उपयोग न करने का निर्णय लिया है ताकि व्यवस्था को धक्का न लगे। इसके बजाय प्राधिकरण ने पूर्ण आबंटन विधि का इस्तेमाल किया है जिसमें वीएसएनएल के लिए बफर उपलब्ध है। इस प्रकार प्रतिस्पर्धी वातावरण धीरे–धीरे बनेगा। वास्तव में सच्चाई यह है कि टेरिफ के निर्धारण के लिए इस समय की गई गणनाओं में एफएलआरआईसी का उपयोग नहीं किया जाता है जिससे वीएसएनएल द्वारा बफर के संबंध में किया जा रहा विरोध केवल इसलिए है कि एफएलएलआरआईसी को लागू करना अव्यवहारिक और बहुत ही जटिल है। इस दृष्टिकोण में जटिलता होने का अर्थ यह नहीं है कि आईपीएलसी सेवाओं के प्रावधान की लागत की सही–सही गणना करने के लिए इसका कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार अन्य परिचालकों/केबल प्रणालियों की भारित औसत लागत के उपयोग की तुलना में वीएसएनएल की पुरानी लागत के उपयोग से प्राप्त बफर को यह उल्लेख करते हुए निरस्त कर दिया गया है कि 'पूंजी की लागत' को बहुत कम बताया गया है। टैरिफ आदेश में दर्शाए गए बफर के आधार पर की गई टिप्पणियों की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

63. लागत गणनाओं के संबंध में वीएसएनएल के प्रस्तुतीकरणों में लागत डाटा, नियोजित पूंजी और बिक्री क्षमता अलग–अलग अवधियों से संबंधित है। वास्तव में, संशोधित गणना (जिसे वीएसएनएल के साथ शेयर किया गया है) में प्राधिकरण ने वीएसएनएल द्वारा मार्च, 2004 के अंत में उपयोग की गई क्षमता तथा मार्च, 2004 को समाप्त अवधि में नियोजित पूंजी पर विचार किया गया है। प्राधिकरण के लिए यह उचित होता कि वह 2003–04 के नियोजित पूंजी को जिसे पृथक लेखों में सूचित किया गया है, को सितम्बर, 2004 में या उसके बाद की अवधि में उपलब्ध क्षमता के रूप में लेता क्योंकि इसमें चालू पूंजीगत कार्य भी शामिल हैं और इस प्रकार इस पर बाद में उपलब्ध क्षमता को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता था। बहरहाल, प्राधिकरण ने ऐसा नहीं किया और इस सीमा तक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए लागत अनुमान में बफर का तत्व मौजूद है। कीमत निर्धारण उन कीमतों के लिए किया जा रहा है जो भविष्य में लागू होंगे। इनका विगत अवधि से कोई संबंध नहीं है और उस संदर्भ में प्राधिकरण को एफएलएलआरआईसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपने दृष्टिकोण में और अधिक सजग होना चाहिए। जिसे इसके द्वारा अधिशेष अधि–लागत (पुराना) को बढ़ाने के लिए नहीं किया गया है। इसके अलावा काफी समय से निवेश और परिचालनिक लागत दोनों के लिए आईपीएलसी सेवाओं की औसत लागत में गिरावट आ रही। प्रौद्योगिकीय उन्नति से भविष्य में भी यह रूख जारी रहने की संभावना है जिसका अर्थ यह है कि अतिरिक्त क्षमता का अधिग्रहण करने की लागत अनुमानित औसत लागत से कम है और भविष्य में भी इसमें काफी गिरावट आने की संभावना है। नए सदस्यों और यहाँ तक इन्कमबेंट की नई क्षमता को ध्यान में रखते हुए कम से कम लागत के अनुमान का उपयोग करने के लिए प्राधिकरण के पास पर्याप्त कारण हैं। बहरहाल प्राधिकरण ने ऐसा नहीं किया है ताकि कम लागत व्यवस्था अपनाई जा सके और लागत आधारित टैरिफ में बफर मौजूद हो।

64. वीएसएनएल ने प्राधिकरण को बताया है कि लागत पूंजी के लिए किए गए मूल्यहास की कीमत अधिक होनी चाहिए क्योंकि मूल्यह्रास की राशि को 18 वर्षों की जीवट आयु के आधार पर लिया जाता है जबकि सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए केबल की आर्थिक आयु केबल 5 से 8 वर्षों की होती है।

65. प्राधिकरण ने नोट किया है कि आईपीएलसी के लिए वास्तविक मूल्यह्रास राशियों का उपयोग किया जा रहा है जोकि विनियमन के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2004 को प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए लेखा परीक्षित पृथक लेखों में वीएसएनएल द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने नोट किया है कि वर्ष 2003–04 के लिए वीएसएनएल की वार्षिक रिपोर्ट में उन्होंने टाटा इंडीकॉम इंडिया सिंगापुर केबल (टीआईआईएस केबल) के संदर्भ में इस प्रकार उल्लेख किया है।

"25 वर्षों की अनुमानित लागत सहित एशिया–पैसेफिक क्षेत्र और पैसेफिक के रास्ते यूएस में भारत के संपर्कता में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए नए केबल लगाना" (वार्षिक रिपोर्ट की पृष्ठ सं. 12 में जोड़ दिया गया है)

66. यदि हम इस जीवट आयु के मूल्य का उपयोग करते हैं तब मूल्यह्रास की लागत और भी कमी होनी चाहिए। बहरहाल, प्राधिकरण द्वारा ऐसा नहीं किया गया और पृथक लेखों के साथ प्रस्तुत लेखा परीक्षित आंकड़ों को मान लिया गया है। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि केबल आमतौर वास्तविक रूप में सामान्यतः अपना कार्य करना तबतक बंद नहीं करता है जबतक कम से कम ट्राई द्वारा किए गए गणना के अनुसार इसकी आयु पूरी नहीं होती। इसके अलावा नई तकनीकी उपलब्ध हो जाने से काफी कम लागत पर केबल की क्षमता में असाधारण वृद्धि की जा सकती है। वीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न डाटा के आधार पर प्राधिकरण भी नोट किया है कि विगत में कीमतें काफी ऊंची रही हैं। (अर्थात् वर्ष 2000 में ई–1 आधी सर्किट आईपीएलसी की कीमत 163.7 लाख रुपए थी, जोकि निवेश पर पहले से ही काफी अधिक प्रतिफल मुहैया करा चुका है।

67. वीएसएनएल का यह भी तर्क है कि प्राधिकरण ने पूंजी की लागत को कम आंका है। प्राधिकरण ने वीएसएलएल के इस कथन की जांच की और नोट किया कि इक्विटी–ऋण संरचना, सामान्य तथा समुचित पूंजी संरचना से काफी भिन्न थी। इस संबंध में परामर्श–पत्र अनुपात के उपयोग पर और टिप्पणियां प्राप्त की गईं। इसके अलावा, परामर्श–पत्र में

आरओसीई एक सामान्य उद्योग के आरओसीई जैसा था। यह एक तरफा नहीं था। इसे वीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर ही तैयार किया गया था। विनियामक के लिए यह उपयुक्त है कि वह उन आंकड़ों (पूंजी संरचना से संबंधित आंकड़ों सहित) में समायोजन करे जो असामान्य हो तथा ऑपरेटर की अकुशलता दर्शायें। प्राधिकरण ने उद्योग में लगे दूसरे ऑपरेटरों के औसत आरओसीई की जांच की और वह आंकड़ा 14% कम आया। वीएसएनएल (VSNL) के ऊपर उल्लिखित प्रस्तुति में यदि हम इक्विटी–ऋण अनुपात को 60:40 में बदलें, जो एक कुशल पूंजी संरचना के लिए एक उपयुक्त अनुपात है, तो आरओसीई, प्राधिकरण द्वारा परामर्श–पत्र में इस्तेमाल की गई राशि के समान ही होगी। वास्तव में, प्राधिकरण ने पहले किसी अन्य संबंध में इक्विटी–ऋण का अनुपात 1:1 लिया। यदि इस अनुपात का इस्तेमाल किया जाए तो आरओसीई और कम 13.46% होगी। वीएसएनएल (VSNL) ने एक विनियम (राजपत्र में प्रकाशित) के अन्तर्गत प्राधिकरण को 31 दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत किए गए लेखा परीक्षित लेखा पृथक्करण विवरण में डब्ल्यूएसीसी (Weighted Average cost of Capital) के रूप में 14.42% का इस्तेमाल किया है। अतः इन्हीं कारणों से प्राधिकरण ने 14.42% के आरओसीई का इस्तेमाल जारी रखा।

68. वीएसएनएल का तर्क है कि पूंजी के लिए जारी किए जाने वाले जीडीआर से प्राप्त धनराशि को शामिल नहीं किया गया है और ऐसी पूंजी को शामिल न करने से लागत में काफी कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त वीएसएनएल ने बताया है कि जीडीआर इश्यू के दौरान प्राप्त धनराशि को शामिल करने के लिए लेखा पृथक्करण विनियम, 2004 का अनुपालन किया गया है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि वीएसएनएल के पृथक्करण लेखा में आईपीएलसी के लिए प्रदत्त पूंजी की राशि उनकी जीडीआर इश्यू से प्राप्त धनराशि में शामिल है जोकि इस समय बैंक में है। इसे लागत से हटा दिया गया है क्योंकि वे आईपीएलसी सेवा, जिसके लिए आकलन किया गया है, के लिए तर्कसंगत नहीं है। ये निधियां आईपीएलसी के परिचालन से संबद्ध नहीं है, और इससे संबंधित लागत को आईपीएलसी के ग्राहकों पर नहीं थोपना चाहिए, अतः इसे छोड़ दिया गया है।

69. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 28.4.05 के टीडीएसएटी के आदेश के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा संबद्ध डाटा/सूचना/रिपोर्टों की वीएसएनएल के साथ भागीदारी की जाती है। प्राधिकरण द्वारा वीएसएनएल के साथ सूचना/डाटा की भागीदारी करने के बाद उनके द्वारा प्राधिकरण से कुछ अनुरोध किया गया जिसमें आईपीएलसी टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए गए कुछ डाटा को प्रतिस्पर्धात्मक बताया गया है। एक आईपीएलसी मूल्य से संबद्ध प्राधिकरण द्वारा विचार की गई पूंजी से संबंधित है और दूसरा प्रमुख मुद्दा अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ से संबंधित है जो कि आईपीएलसी मूल्य से संबद्ध है। प्राधिकरण ने वीएसएनएल के दावों की सत्यता जानने के लिए उसकी लेखा पुस्तिका तथा अन्य दस्तावेजों का सत्यापन करना उचित समझा। ट्राई के अधिकारियों की एक टीम द्वारा किए गए सत्यापन क्रियाकलाप केवल सेवा प्रदाताओं के मुद्दों को सत्यापित नहीं करता बल्कि संदेह के अन्य क्षेत्रों को उजागर करता है। वीएसएनएल द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से विभिन्न उत्पादों के बैंडविड्थ प्रभारों के आबंटन का आधार और संयुक्त लागतों/आम लागतों से संबंधित खर्च का अनुपातिक मापदंड पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाए। इसके अतिरिक्त, आईपीएलसी के लिए उपयोग किए गए सबमैरिन केबल बैंडविड्थ की वास्तविक क्षमता, जिसके बारे में वीएसएनएल द्वारा विगत में कई बार रिपोर्ट की गई है और जिसका सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पता चला है, असंगत है।

70. प्राधिकरण ने, लागत के आकलन और उस डाटा के विवेचन के लिए उपयोग में लाए गए डाटा और वीएसएनएल द्वारा पिछले अवसरों पर प्राधिकरण को उपलब्ध कराए गए डाटा और वे डाटा जो अब सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पाए गए हैं, पर वीएसएनएल के प्रस्तुतीकरण पर विचार किया है। ट्राई के अधिकारियों के सत्यापनों के निष्कर्षों की जानकारी वीएसएनएल को दी गई। बहियों तथा अन्य दस्तावेंजों के सत्यापन के लिए तैनात ट्राई की टीम की रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों पर वीएसएनएल के उत्तर की ट्राई द्वारा जांच की गई। वीएसएनएल द्वारा निरीक्षण (ट्राई के अधिकारियों द्वारा) रिपोर्ट का किया गया विश्लेषण भी संगत गणना के साथ वीएसएनएल को उपलब्ध कराया गया। चूंकि इन मुद्दों में वीएसएनएल के अतिसंवेदनशील वाणिज्यिक डाटा शामिल होते हैं, इसलिए प्राधिकरण इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में वीएसएनएल

की लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों के सत्यापन की विस्तृत जांच करने में भागीदारी करना नहीं चाहता है। बहरहाल, ट्राई के अधिकारियों द्वारा सत्यापनों के निष्कर्ष के बारे में वीएसएनएल को पहले बता दिया गया है। ये मुद्दे और अन्य संबद्ध मुद्दों जैसे विश्व के इस भाग में सबमैरिन केबल क्षमता का अधिग्रहण/संस्थापन/विस्तारण और मांग की बदलते स्वरूप और आईपीएलसी मूल्यों के लिए इसके प्रभावों के संबंध में आईपीएलसी टैरिफ की अगली समीक्षा में प्राधिकरण द्वारा निपटाया जाएगा।

71. तदनुसार प्राधिकरण भारत में आईपीएलसी सेवाओं के लिए अधिकतम टैरिफ फ्रेमवर्क को निम्नानुसार दोहराया हैः–

क्षमता	**कीमत (लाख रुपयों में)**
ई–1	13
डीएस–3	104
एसटीएम–1	299

E 1 से कम क्षमता के लिए कीमतें

72. E 1 से नीचे की छोटी क्षमताओं के लिए आईपीएलसी क्षमताओं के लिए अलग से अधिकतम कीमत निर्धारित न करने का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि छोटी क्षमताएं जो कुल अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ मांग का अब बहुत ही कम भाग है वे भविष्य में बहुत कम हो जाएंगी। अतः इस प्रकार की क्षमताओं के टैरिफ को छोड़ दिया गया है।

भिन्न उपयोग के लिए कीमतें

73. परामर्श–पत्र में उठाया गया दूसरा मुद्दा विभिन्न उपयोगों के लिए अर्थात् वॉयस अथवा डाटा के लिए इस अधिकतम टैरिफ को लागू करने से संबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है

कि सम्बद्ध आईपीएलसी टैरिफ की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से संबंधित लागत आधारित औचित्य में उस स्थिति में कोई अन्तर नहीं है जब इसका उपयोग विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए किया जाता है। अधिकांश स्टेकहोल्डरों का मत था कि प्रस्तावित टैरिफ की अधिकतम सीमा समान होनी चाहिए, चाहे इसे वॉयस के लिए इस्तेमाल किया जाए या डाटा के लिए। उपयुक्त को देखते हुए प्राधिकरण ने आईपीएलसी हॉफ सर्किट के टैरिफ, चाहे उसका इस्तेमाल वॉयस के लिए हो या डाटा के लिए, समान रखने का निर्णय लिया है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसो0 ऑफ इंडिया ने अपने पत्र में कहा कि अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी की लागत का सारा भार आईपीएलसी पर डालना उचित नहीं है। इस संबंध में प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि आईपीएलसी के लिए लागत आधारित कीमत का आकलन करने के लिए 2003–04 के लिए पृथक लेखों, जिनकी आईपीएलसी सेगमेंट के लिए लेखा परीक्षा की गई थी, पर ही निर्भर किया गया। पृथक लेखों में अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी के बिजनेस के लिए इसी प्रकार के लागत के ब्यौरे अलग से उपलब्ध थे इसलिए सीओएआई का कथन सही नहीं है। वीएसएनएल द्वारा आईएलडी कॉलों के लिए आईपीएलसी का इस्तेमाल करने की स्थिति में वीएसएनएल को ऐसे उपयोग के लिए वही प्रभार लगाना चाहिए जो प्रभार दूसरों पर लागू होता है।

सैटेलाइट आईपीएलसी के लिए टैरिफ प्रविरिति

74. जैसा कि पद्धति में उल्लेख किया गया है सैटेलाइट आईपीएलसी से संबंधित लागत पर विचार नहीं किया गया है इसलिए सैटेलाइट आईपीएलसी के टैरिफ प्रविरिति रखी गई है।

हॉफ सर्किट आईपीएलसी के लिए मानक टैरिफ अनिवार्य करना।

75. आईपीएलसी सेवा के प्रावधान में दो तत्व शामिल हैं अर्थात् भारतीय छोर का एक हॉफ सर्किट तथा दूरस्थ छोर का दूसरा हॉफ सर्किट। आईपीएलसी के लिए ट्राई के विनियम/टैरिफ आदेश में आईपीएलसी के उस नजदीकी छोर वाला भाग ही शामिल किया

जा सकता है, जिसकी भारत के किसी लाइसेंसधारी आईएलडीओ द्वारा पेशकश की जाती है। भारत में आईएलडीओएस, विदेशी वाहक के साथ वाणिज्यिक व्यवस्थाएं करके आईपीएलसी की पूर्ण सर्किट की सेवाएं प्रदान करते हैं, परन्तु ट्राई का टैरिफ आदेश भारत से सम्बद्ध नजदीकी छोर के हॉफ सर्किटों पर ही लागू होता है। अतः प्राधिकरण ने एक ऐसे मानक टैरिफ पैकेज का अधिदेश दिया है जिसमें प्रत्येक कोटि तथा गंतव्य, जिसके लिए आईएलडीओएस द्वारा पूर्ण सर्किट सेवाओं की पेशकश की जाती है, के लिए हॉफ सर्किट की अधिकतम टैरिफ की पेशकश की जाएगी। इससे प्राधिकरण, सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ आदेश के अनुपालन पर नजर रख सकता है। बहरहाल, आईएलडीओएस, बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के अध्यधीन कोई अन्य वैकल्पिक पैकेज की पेशकश भी कर सकते हैं। अनिवार्य मानक पैकेज सहित सभी टैरिफ पैकेजों में से चुनाव करने का अधिकार आईपीएलसी सेवा के खरीदार का होगा।

निष्कर्ष

76. इस संदर्भ में प्राधिकरण, टैरिफ की कमी के परिणामस्वरूप भारत में मोबाइल टेलीफोनी के विकास को ध्यान में रखता है। इसी प्रकार आईपीएलसी के लीज प्रभारों में कमी होने से इसका भी भारी विकास होगा। भारत में विकास का अनुभव यह है कि कम कीमत होने से वॉयस टेलीफोनी के सब्सक्राइबरों में भारी वृद्धि हुई और ऐसी आशा करना उचित ही होगा कि यही कहानी ब्राडबैंड/इंटरनेट और दूसरी डाटा सेवाओं, जो इन्टरनेशनल बैंडविड्थ पर पूरी तरह निर्भर हैं, में भी दोहराई जाएगी। अतः आईपीएलसी के लिए लागत आधारित टैरिफ का निर्धारण करने के लिए प्राधिकरण का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हो जाता है, परन्तु प्राधिकरण द्वारा अधिदेशित कम कीमतों के कारण मांग में वृद्धि से ऑपरेटरों की क्षमता का उच्चतर उपयोग होगा, जिसका गौण प्रभाव कीमत के स्तर को नीचे लाएगा। व्याख्यात्मक ज्ञापन में कई ऐसे अन्य कारण दिए हैं, जिनकी वजह से आईपीएलसी के टैरिफ की अधिकतम सीमा के संबंध में प्राधिकरण का हस्तक्षेप जरूरी है।

77. प्राधिकरण का मत है कि टैरिफ की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से संबंधित प्रक्रिया को कई बार बढ़ाया गया है ताकि आईपीएलसी प्रदाताओं द्वारा बार–बार किए जाने वाले विभिन्न अनुरोधों को समाहित किया जा सके और आशा की जाती है आईपीएलसी सेवा प्रदाता इस स्तर पर विनियामक हस्तक्षेप से सहमत होंगे और जब कभी इसे कार्यान्वित किया जाएगा इसे निर्धारित टैरिफ पर लागू करेंगे और रिपोर्टिंग की मौजूदा आवश्यकताओं के अनुसार इसके बारे में सूचित करेंगे।

अनुबंध 'क' का परिशिष्ट–I

मुख्य टिप्पणियों का सार

परामर्श पत्र (2004 का 10) पर हितधारियों की विभिन्न टिप्पणियां संक्षेप में नीचे दी गई हैं:

(क) क्या आईपीएलसी (हॉफ सर्किट) को आगे विनियमित किया जाना चाहिए?

- उपयोगकर्ता समूह और उपभोक्ता संगठनों की राय थी कि जब तक बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा स्थापित नहीं हो जाती तब तक आईपीएलसी के टैरिफ विनियमित किए जाए।

- सामान्य तौर पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने इस बात पर अपनी चिन्ता व्यक्त की कि 2002 में आईएलडी सेक्टर की शुरूआत हो जाने के बावजूद आईपीएलसी के कारोबार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा नहीं आई है और इसलिए उनकी राय थी कि प्राधिकरण को न केवल आईपीएलसी के टैरिफ विनियमित करने चाहिए बल्कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए भी और कदम उठाने चाहिए।

- बहुत से हितधारियों द्वारा इस समय आईपीएलसी के टैरिफ विनियमित करने के लिए ट्राई का हस्तक्षेप इस आधार पर आवश्यक समझा क्योंकि लागत पर आधारित कीमतों पर आईपीएलसी की उपलब्धता से इंटरनेट तथा ब्राडबैंड सेवाओं का विकास होगा और उनकी पैठ बढ़ेगी।

- परामर्श पत्र पर अपनी प्रस्तुति में एक सेवा प्रदाता ने कहा कि ट्राई द्वारा आईपीएलसी के टैरिफ का निर्धारण किया जाना आवश्यक है जिनसे भारत में

आईपीएलसी की कीमतें अधिक वहनीय बनें और ये एशिया–पैस्फिक क्षेत्र में मौजूद बाजार की कीमतों के अनुरूप हों।

- एक राय यह थी कि इंटरनेट के उपयोग के उद्दीपन तथा उसे बढ़ावा देना और वहनीय ब्राडबैंड सेवाओं की उपलब्धता अन्य बातों के साथ–साथ कम कीमत की इंटरनेशनल बैंडविड्थ की अभिगम्यता पर निर्भर करता है क्योंकि आईपीएलसीएस इन सेवाओं के लिए मुख्य अन्तरराष्ट्रीय वाहक प्लेटफार्म है।

- एक राय यह भी व्यक्त की गई कि भारत में आईपीएलसी की उंची कीमतें भारतीय अन्तरराष्ट्रीय डाटा राजस्व की संभावित विकास के मार्ग में बाधक है और इससे क्षमता की कम मांग का अनुमान भी लगता है। इस प्रकार, आईपीएलसी की उंची कीमतें, उपभोक्ता सेवाओं की मांग भी प्रभावित करती हैं जो अन्यथा बड़े पैमाने पर बैंडविड्थ क्षमता की व्यवस्था करते।

- जब तक आईपीएलसी की कीमतों को कम नहीं किया जाता तब तक बीपीओ सेवाओं के ग्राहक बड़े पैमाने पर उन देशों की ओर मुड़ेंगे जो कम कीमत पर बीपीओ सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करेंगे। इसका भारत में बीपीओ उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

- ट्राई को टैरिफ की अधिकतम सीमा निर्धारित करनी चाहिए ताकि वीएसएनएल (VSNL) की दरें लागत आधारित हों। समय–समय पर टैरिफ की समीक्षा की जानी चाहिए परन्तु जब तक यह न समझा जाए कि बाजार की प्रभावी शक्तियां आईपीएलसी की दरों पर पर्याप्त दबाव डाल सकती हैं तब तक इसे बनाया रखा जाना चाहिए।

- एक आईएलडीओ की टिप्पणी थी कि कीमत, बाजार की मांग तथा सप्लाई पर निर्भर करता है इसलिए बाजार की शक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। परन्तु विनियामक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे ऑपरेटर जिनके पास काफी क्षमता हो (Bottleneck सुविधाएं) वे बैंडविड्थ सप्लाई प्रतिबंधित न करें और इस प्रकार कृत्रिम रूप से कीमतों को न बढ़ाए। तदनुसार, विनियामक को Bottleneck सुविधाओं जैसे कि महत्वपूर्ण ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले लैडिंग स्टेशनों की आसान अभिगम्यता सुनिश्चित करनी चाहिए।

- इन्कमबेंट की राय थी कि बाजार की शक्तियों को कीमत निर्धारित करने देना चाहिए और इस प्रकार आईपीएलसी की कीमतों को विनियमित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वीएसएनएल (VSNL) की राय थी कि बाजार को विनियमित करने का कोई भी प्रयास निवेश को प्रभावित करेगा और इस प्रकार इससे विकास भी प्रभावित होगा। उनका यह भी मानना था कि इससे ग्राहकों को पैकेजों की पेशकश करने में जटिलता भी आ सकती है।

- इन्कमबेंट का मत था कि सप्लाई बढ़ने से अगले 12–18 महीने में भारत में आईपीएलसी की कीमतें 30% तक घटने की संभावना है।

- वीएसएनएल (VSNL) ने कहा कि आईटी, आईटी–ईएस तथा ब्राडबैंड सेवाओं की कीमत संरचना का एक बहुत छोटा भाग ही आईपीएलसी की कीमत से सम्बद्ध है।

(ख) क्या प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कटौती पर्याप्त है, पर्याप्त से कम है या यह बहुत ज्यादा है

- एक आईएलडीओ ने कहा कि ई 1 सर्किट के लिए 12 लाख रुपये की प्रस्तावित टैरिफ की अधिकतम सीमा बहुत ही ज्यादा है। वीएसएनएल (VSNL) के वर्तमान

टैरिफ पर 15% से 20% की कटौती अधिक यथार्थ है। इसी प्रकार, डीएस 3 क्षमता के लिए प्रस्तावित किए गए ई 1 की अधिकतम सीमा के 8 गुणा को अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार के आधार पर संशोधित कर ई1 का 11 गुणा किया जाना चाहिए।

- एक दूसरे आईएलडीओ की राय थी कि प्राधिकरण द्वारा टैरिफ में प्रस्तावित कटौती प्रभावकारी है। तथापि, हॉफ सर्किट के टैरिफों को उन देशों की तुलना में जो बीपीओ/आईटीईएस सेक्टर में भारत से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, की तुलना में अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए। ऐसा कारोबार करने का आर्कषक वातावरण मुहैया करने के लिए नितान्त आवश्यक है।

- टेलीकॉम सेक्टर के एक स्टैंड अलोन प्लेयर ने यह राय व्यक्त की कि यद्यपि विभिन्न सर्किटों की कीमतों का आकलन करने के लिए लागत+पद्धति अपनाई जा सकती है, परन्तु इसे अन्तरराष्ट्रीय कीमतों के लिए बेंचमार्क माना जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एकाधिकार प्राप्त सेवा प्रदाता वीएसएनएल (VSNL) को उसकी अकुशलता से लाभ प्राप्त न हो।

- आईएसपीएआई की राय थी कि परामर्श पत्र में प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव की गई कटौती बहुत कम है और यह बहुत विलम्ब से की गई है। यह कटौती यह देखते हुए भी बहुत कम है कि आईएसडी टैरिफ में तेजी से आई कमी के लाभ को आईएलडीओएस ने जानबूझकर आईपीएलसी के उपयोगकर्ताओं को प्रदान नहीं किया।

- सीओएआई ने अपनी लिखित टिप्पणी में कहा कि प्राधिकरण द्वारा अपने परामर्श पत्र में प्रस्तावित कटौती बहुत कम है और यह बहुत विलम्ब से की गयी है। यह कटौती यह देखते हुए भी बहुत कम है कि आईएसडी टैरिफ में तेजी से आई कमी

के लाभ को आईएलडीओएस ने जानबूझकर आईपीएलसी के उपयोगकर्ताओं को प्रदान नहीं किया।

- एक आईएसपी ने टिप्पणी की कि वीएसएनएल (VSNL) की आईपीएलसी टैरिफ का प्रारंभिक निर्धारण करते समय इसी प्रकार के आईपीएलसी क्षमताओं के लिए एशिया–पैस्फिक क्षेत्र में अन्यत्र प्रभारित की जाने वाली बाजार दरों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।

(ग) पद्धति तथा संबंधित मुद्दे, कीमत–मल्टीपल सहित

- एक आईएलडीओ की राय थी कि टैरिफ के निर्धारण के लिए प्राधिकरण का लागत आधारित दृष्टिकोण उचित प्रतीत होता है, परन्तु कुछ स्थानों पर अनुमान ज्यादा लगाए गए हैं।

- आईएसपीएआई की टिप्पणी यह थी कि अधिकांश अन्तरराष्ट्रीय केबल कई देशों से गुजरते हैं इसलिए निवेश संबंधी निर्णय भारत जैसे एक देश की संभावनाओं तथा वर्तमान बाजार पर आधारित नहीं होता है। लागत के आकलन के लिए यह पहलू महत्वपूर्ण हो जाता है।

- सीओएआई ने टिप्पणी की कि आईएलडी की समस्त लागत केवल आईपीएलसी पर डालना अनुचित है।

- एक विदेशी वाहक ने कहा कि ट्राई, प्रारंभिक चरण में प्रस्तावित दर कटौती को अपनाए परन्तु बाद में पद्धति की पूरी एलआरआईसी का अध्ययन किया जाना चाहिए।

- एक दूरसंचार सेवा प्रदाता ने कहा कि पद्धति उचित प्रतीत होती है, परन्तु यह समझा जाना चाहिए कि संस्थापित क्षमता काफी अधिक है। नाममात्र की क्षमता का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि संस्थापित क्षमता उपलब्ध की जाए तो प्रति ई 1 लागत काफी कम होगी। यह उल्लेखनीय है कि मांग है और जैसे ही क्षमता उपलब्ध होती है, बाजार उसे समाहित कर लेता है।

- वीएसएनएल (VSNL) ने यह टिप्पणी की कि पत्र में यह माना गया है कि कुल उपलब्ध केबल क्षमता पहले दिन ही बेच दी जाएगी और यह अगले 15 वर्ष तक बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी और इसमें कोई रिक्ति या अनिरन्तरता नहीं होगी। यह तथ्य से काफी दूर है। व्यवहार में यह मानना सही नहीं है कि अगले 15 वर्षों में कीमतों में कोई कमी नहीं होगी। यह मानना भी सही नहीं है कि Entity की संपूर्ण परिचालनिक लागत वसूल करने के लिए 10% का परिचालिक व्यय पर्याप्त है। इस पद्धति में परिसम्पत्ति की वास्तविक कार्यकाल (Life) तथा और आर्थिक कार्यकाल के बीच अन्तर नहीं किया गया है।

- वीएसएलएल (VSNL) ने परामर्श–पत्र में निहित पद्धति में मानी गई कुछ बातों पर भी टिप्पणी की। इनमें ट्राई द्वारा मानी गई कुल लागत में सैटेलाइट लागत का भाग पूंजीगत लागत के अनुमान के अंतर्गत ज्यादा मानना तथा पूंजीगत लागत का कम अनुमान तथा पर्यवेक्षण तथा प्रशासनिक प्रभारों की व्यवस्था के लिए कम प्रावधान मानना शामिल है।

- वीएसएनएल (VSNL) ने यह भी टिप्पणी की कि यद्यपि प्राधिकरण ने एनएलडी कीमत निर्धारण के लिए 1:21:63 का अनुपात अनुमोदित किया है, परन्तु आईपीएलसी के कीमत निर्धारण के लिए इसने 1:8:23 का ही प्रस्ताव किया है। बहरहाल दोनों सेवाओं में एक ही किस्म की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा

रहा है और इनमें मल्टीप्लेक्सिंग/डिमल्टीपलेक्सिंग की संबद्ध लागत भी समान अनुपात में होती है।

- एक दूसरे आईएलडी ने यह उल्लेख किया कि वे इस पद्धति से सहमत है कि एक ई 1 को बैंडविड्थ के उच्चतर मल्टीपल के लिए बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तथापि, ई 1 की लागत तथा ओएण्डएम प्रभार तथा इसकी उच्चतर क्षमताओं में कोई रेखीय (Linear) संबंध नहीं होता है। अतः बैंडविड्थ मल्टीपल को लागत मल्टीपल के रूप मानना उचित नहीं है। लागत मल्टीपल के लिए अन्तरराष्ट्रीय मानक भारत के मानक से भिन्न हो सकते हैं, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। अतः उन्होंने सिफारिश की कि विद्यमान अन्तरराष्ट्रीय अनुपात स्वीकार किया जाना चाहिए।

- नैसकॉम के विचार में अपनाई गई पद्धति से अनुपात सही दिशा में बन रहा है और यह एक अच्छी शुरूआत है। परन्तु जब डी–एस–3 तथा एसटीएम–1 का उपयोग बढ़ेगा, तब समान बेंचमार्क तथा मौजूदा मल्टीपल वैध नहीं रहेंगे और इनकी समय–समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता होगी। उस समय ट्राई को उपयोग कारक, सेवाओं की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता और संकुलन के स्तर जैसे कारकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी।

- निवेश का विश्लेषण करने वाली एक फर्म ने यह टिप्पणी की कि वे लागत मूल्य में ट्राई द्वारा निर्दिष्ट कीमत–मल्टीपल से सहमत हैं क्योंकि इनका युक्तिसंगत आधार है और ये दूसरे देशों में तदनरूपी मल्टीपल के अनुरूप भी हैं।

- एक दूरसंचार सेवा प्रदाता ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र के तेजी से बदलते हुए डायनेमिक्स को देखते हुए जो भी टैरिफ ट्राई निर्धारित करेगी उसकी 12 माह बाद समीक्षा की जानी चाहिए।

- अधिसूचित अधिकतम सीमा की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। यह जांच वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो अधिकतम सीमा संशोधित की जानी चाहिए। बहरहाल, यदि वर्ष में एक बार "रिटेल माइनस" कीमत शुरू कर दी जाती है तो तब आपवदिक स्थिति में हस्तक्षेप करने के अलावा, समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है।

- इस मुद्दे पर कि चाहे अंतिम उपयोग (End use) वॉयस अथवा डाटा कुछ भी क्यों न हो क्या समान टैरिफ लागू किया जाना चाहिए अधिकांश स्टेकहोल्डरों की राय थी कि डाटा अथवा वॉयस के लिए आईपीएलसी मुहैया कराने की लागत में कोई अन्तर नहीं होता है और यदि अन्तर होता भी है तो यह बहुत ही कम होता है। अतः सम्बद्ध आईपीएलसी के लिए कोई लागत आधारित औचित्य नहीं है। भारतीय व्यापार तथा उपभोक्ताओं दोनों को कम कीमत पर सामान्यतः पीसीटीएन आधारित अन्तरराष्ट्रीय वॉयस सेवाओं के विस्तार तथा उच्चतर गुणवत्ता मानकों का लाभ मिलेगा।

- उद्योग के एक एसोशिएशन ने कहा कि आईएलडीओएस लाइसेंस की शर्तों के अनुसार Bottleneck सुविधाएं सभी उपयोगकर्ताओं तथा दूसरे आईएलडीओएस को देने के लिए वचनबद्ध हैं। इस समय केबल क्षमता एक कठिनाई है क्योंकि भारत में सीमित लैंडिंग स्टेशन हैं। आईएलडीओएस, खासतौर पर ऐसे आईएलडीओएस, जिनके पास "इन्कमबेंट" सुविधाएं हैं, को दूसरे आईएलडीओएस को रियायती दरों पर पेशकश करने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि क्षमता की उच्चतर आवश्यकता प्रतिबिम्बित हो और इस Bottleneck सुविधा की भागीदारी को भी बढ़ावा मिले।

- इन्कमबेंट ने कहा कि उन्होंने विगत में उस समय आधारभूत संरचना पर निवेश किया जब देश को इसकी आवश्यकता थी और जब कीमतें बहुत ज्यादा थी। जब

ये अपने प्रतिस्पर्धियों को आईपीएलसी सेवाओं की पेशकश करें तो उन्हें अपने नेटवर्क की कम्पोजिट लागत की भरपाई करनी होगी। एसे प्रतिस्पर्धियों (आईएलडीओएस) जो सेवाओं की बिक्री करते हैं, के टैरिफ, उन कार्पोरेट ग्राहकों, जो सेवाओं की बिक्री नहीं करते हैं, के टैरिफ से भिन्न रखने की आवश्यकता है।

(घ) अन्य टिप्पणियां

- लम्बी अवधि में क्षमता वृद्धि सहित लागत के सभी तत्वों के लागत के आधार पर फारवर्ड लुकिंग दीर्धकालिक वर्द्धमान लागत का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसके लिए नेटवर्क संबंधी अर्थशास्त्र की गहरी समझ अपेक्षित है। मॉडल अनुमान विषयनिष्ठ होते हैं।

- एलआरआईसी सेवा अर्थशास्त्र को सही–सही प्रकार से प्रतिबिम्बित करता है और यह अकुशल इन्कमबेंट की रक्षा नहीं करता है।

- जहां बैंडविड्थ की मांग रहती है उन रूटों पर कम कीमत देखे जाते हैं और सप्लाई प्रचुर हो जाती है।

- विभिन्न मार्केटों में मौजूद क्षमता के परिणामस्वरूप 'हब' (जैसे कि हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम) तथा "स्पोक्स" (जैसे कि थाइलैंड, इंडोनेशिया, ब्राजील) बनते हैं। हब से स्पोक के अथवा एक स्पोक से दूसरे स्पोक की तुलना में एक हब से दूसरे हब की कीमतें कम होती हैं।

- रूटों के अनुसार कीमतें अलग–अलग होती हैं।

- परामर्श–पत्र में अपनाई गई पद्धति सही नहीं है क्योंकि इसमें 28% की पूंजी वसूली तथा 18 वर्ष की परिसंपत्ति का कार्यकाल लिया गया है।

- मौजूदा लागत तथा वर्द्धमान दोनों के हिसाब से स्वामित्व वाली तथा कंसोर्टियम केबल की लागत अलग–अलग होती है।

- कसोर्टियम केबल की कीमतों में परिवर्तन की बहुत कम लोचशीलता होती है।

- अन्तरराष्ट्रीय कीमतों से तुलना करना सही नहीं है क्योंकि ये कीमतें दिवालियापन तथा परिसंपत्तियों की सूचीबद्ध कीमतें प्रतिबिम्बित करती हैं।

अनुबंध 'क' का परिशिष्ट 2

प्रतिस्पर्धा के मार्ग में बाधक कारक

प्लेयरों की सीमित संख्या

भारत में, अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी (आईएलडी) सेगमेंट 2002 में प्रतिस्पर्धा के लिए खोला गया था। विदेश संचार निगम लि0 (VSNL) एक इन्कमबेंट ऑपरेटर है, जिसके पास मुंबई, कोचीन तथा चेन्नई में लैंडिंग स्टेशन की सुविधाएं हैं। दूसरे आईएलडीओएस जो सबमेरीन केबल बैंडविड्थ सेवाएं भी सप्लाई करते हैं वे भारती इन्फोटेल, रिलायंस इन्फोकॉम हैं। भारती इन्फोटेल के पास चेन्नई में लैंडिंग स्टेशन की सुविधा है। भारती इन्फोटेल ने सूचित किया है कि आईपीएलसी में उनका परिचालन केवल 'नॉन–रिस्टोरेबल' श्रेणी तक ही सीमित है। अभी तक रिलायंस इन्फोकॉम ने अपनी केबल लैंडिंग सुविधा की स्थापना नहीं की है। कुछ और समय तक वीएसएनएल (VSNL) के आईपीएलसी बाजार में प्रभुत्व बनाए रखने की संभावना है। इस प्रकार, भारत में आईपीएलसी में मौजूदा बाजार संरचना इस प्रकार की है जिसमें केवल तीन की सक्रिय प्लेयर हैं और उमें केवल दो के पास ही लैंडिंग सुविधाएं हैं। यह देखा गया है कि बहुत से देशों में प्लेयरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और अधिकांश ऑपरेटर गैर–सुविधा आधार वाले ऑपरेटर होते हैं। इस समय भारत में क्षमता की पुनः बिक्री की अनुमति नहीं है क्योंकि अतिरिक्त क्षमता निर्माण पर बल दिया जा रहा है। नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक स्थान में बैंडविड्थ प्रदाताओं (पुनः बिक्री करने वाले सहित) की संख्या दी गई है :

स्थान	बैंडविड्थ प्रदाताओं की संख्या
लंदन	33
यूएसए–न्यूयार्क	32
जर्मनी	32
फ्रांस	24
दक्षिण कोरिया	14
भारत	3

स्रोतः एर्नस्ट एण्ड यंग / एनआरए बैवसाइट

सुविधाओं की अभिगम्यता

बहुत सी दूरसंचार सेवाओं के लिए सबमेरीन केबल लैंडिंग स्टेशनों की अभिगम्यता को एक आवश्यक साधन माना जाता है। अनावश्यक अभिगम्यता प्रतिबंधों से अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराने के लिए ऑपरेटर की प्रतिस्पर्धा सीमित होती है। इस प्रकार, सबमेरीन केबल लैंडिंग स्टेशन दूरसंचार की एक महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर है और प्रयास किया जाना चाहिए कि ये दूरसंचार की व्यवस्था के मार्ग में बाधक न बनें। अभिगम्यता के मार्ग की रूकावटों से दूरसंचार ऑपरेटरों की प्रतिस्पर्धा बाधित होती है और यह दूर–संचार बाजार के स्वस्थ विकास के लिए हितकर नहीं है। प्राधिकरण को कई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें कहा गया कि सुविधाओं की अभिगम्यता में कठिनाई पैदा कर प्रतिस्पर्धा प्रभावित की जा रही है।

वीएसएनएल (VSNL) का केबल लैंडिंग स्टेशनों तथा सम्बद्ध सुविधाओं पर नियंत्रण बने रहने से कठिनाई पैदा होती है क्योंकि इन्कमबेंट दूसरे ऑपरेटरों के प्रवेश को रोकता है अथवा इसमें विलम्ब करता है (अथवा कुशल आपरेशन)। अभिगम्यता की समस्या का सामना न केवल आधारभूत केबल ऑपरेटर करते हैं बल्कि यह समस्या उन ऑपरेटरों के सामने भी रहती है, जिन्होंने केबल प्रणाली में क्षमता अर्जित कर ली है परन्तु जो लैंडिंग स्टेशन की क्षमता

प्राप्त करना चाहते हैं। उद्योग के साथ वार्ता से पता चलता है कि भारत में केबल लैंडिंग स्टेशन सुविधा की स्थापना करने के लिए न केवल भारी निवेश की आवश्यकता है बल्कि यह एक बहुत समय लगने वाला कार्य भी है, जिसके लिए बहुत सी स्वीकृतियां ली जानी होती हैं, जिसमें सुरक्षा आदि की स्वीकृति भी शामिल है। इस प्रकार केबल लैंडिंग स्टेशनों की अभिगम्यता वास्तव में ऐसे गैर–कीमत कारक हैं जिनका सहारा सप्लायर द्वारा प्रतिस्पर्धा प्रभावित करते हुए लिया जाता है।

प्राधिकरण ने नोट किया है कि भारत में आईपीएलसी बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए कुछ अन्य कदम उठाने अपेक्षित हैं। इस संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2005 की परामर्श–पत्र सं. 5 जारी करके एक अलग से परामर्श प्रक्रिया की पहल की गई है।

अनुबंध 'क' का परिशिष्ट 3

बेंचमार्क के साथ भारतीय आईपीएलसी टैरिफ की तुलना

1) सूचीबद्ध कीमतों से तुलना

1. आईपीएलसीएस के लिए भारत में मौजूद टैरिफों की तुलना अन्तरराष्ट्रीय बेंचमार्क और वीएसएनएल (VSNL) के पृथक लेखों में उपलब्ध लागत के आंकड़ों का इस्तेमाल करके निकाले गए लागत आधारित अनुमान से की गई। घरेलू तथा अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ गहन विचार विमर्श करके प्राधिकरण ने बैंडविड्थ के लिए अन्तरराष्ट्रीय लीज कीमतों के विभिन्न पहलुओं, जिसमें अन्तरराष्ट्रीय बेंचमार्क का कार्य, सब–मेरीन नेटवर्क के लिए केबल बिछाने की लागत के रूझान, उन विभिन्न देशों में जहां कीमतें प्रतिस्पर्धी हैं, बाजार की संरचना, आईपीएलसी सेक्टर को शासित करने वाला विनियामक वातावरण आदि भी शामिल है, की जांच की।

2. विभिन्न कारकों से पिछले पांच से ज्यादा वर्षों से बैंडविड्थ के अन्तरराष्ट्रीय बाजार में अपस्फीति रही है। पूरे क्षेत्र में कीमतों के रूझान की तुलना के प्रयोजन के लिए अब एसटीएम–1 लीज कीमत, ज्यादातर प्रयोग किया जाने वाला डिनोमिनेटर है। आगे, पूरे क्षेत्र में एसटीएम–1 के लीज कीमतों के रूझानों की तुलना की गई है। यह पाया गया है कि ट्रांस–अटलांटिक क्षेत्र में एसटीएम–1 की कीमतों का माध्य 2000 में 70%, 2001 में 65%, 2002 तथा 2003 प्रत्येक में 26% और 2004 में 25% कम हुआ। ट्रांस पैस्फिक क्षेत्र में एक प्रतिनिधिक रूट पर एसटीएम–1 की कीमतों का माध्य 2003 में 56% तथा 2002 में 40% गिरा। यूरोप–एशिया क्षेत्र में एसटीएम–1 सर्किट की कीमतों का माध्य 2003 में लगभग 42% गिरा जो पिछले वर्ष आई गिरावट के समान है। एशिया में एसटीएम–1 लीज कीमतों का माध्य 2003 में 50% से 60% गिरा (स्रोतः प्रीमेट्रिका, आईएनसी, 2004 वाल 1ःसबमेरीन नेटवर्क)।

प्रीमेटिका, 2005 की रिपोर्ट वर्ष 2004 में कई क्षेत्रों और मार्गों में आईपीएलसी में और गिरावट होने के साक्ष्यों को दर्शाता है। इस पृष्ठभूमि में भारत से आरंभ होने वाले एसटीएम–1 के लिए वर्ष 2002 से 2005 (जून, 2005 तक की अवधि के दौरान मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) (भारत से यूएसए) के संदर्भ में लीज कीमत में लगभग 12.5% की गिरावट हुई है और भारत से आरंभ होने वाले डीएस–3 तथा ई–1 क्षमताओं में क्रमशः 12.5% और 15.7% (भारत से यूएसए) की गिरावट आई। उपर्युक्त की भारतीय कीमतों से तुलना करने पर पता चलता है कि भारत में, सेवाओं की अन्तरराष्ट्रीय क्षमता की लीज कीमत की गिरावट की सीमा दुनिया के दूसरे भागों की गिरावट की सीमा से काफी कम है।

3. आईपीएलसी सेवा प्रदान करने की लागत के रूझानों की समीक्षा भी की गई थी और यह पाया गया कि मुख्यतः प्रौद्योगिकी की उन्नति तथा इक्यूमेंट सप्लायर के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण केबल निर्माण तथा सबमेरीन नेटवर्क के अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों के लागत में भारी कमी आई है। उदाहरण के लिए बाजार की प्रतिस्पर्धा बने रहने के लिए केबलों का अपग्रेडिंग एक लागत प्रभावी तरीका है। प्रौद्योगिकी की उन्नति, जैसे कि नई मोड्येलेशन तकनीक आदि से पुराने केबल उनके प्रारंभिक अभिकल्पित क्षमता से आगे भी काम करने की क्षमता अर्जित करते हैं। इस प्रकार केबल प्रणाली में अपग्रेशन महत्वपूर्ण पहलू हैं क्योंकि इनसे ऑपरेटर नए केबल के निर्माण करने के बजाय बहुत ही कम लागत पर क्षमता जोड़ लेते हैं। यह इस तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि 2003 में सबमेरीन केबल के निर्माण की लागत 1 बिलियन अमेरीकी डालर से कुछ ज्यादा थी जबकि 2001 में यह 12 बिलियन अमेरीकी डालर था (स्रोत प्रीमेट्रीका आईएनसी 2004 वाल 1ः सबमेरीन नेटवर्क)। यह न केवल बैंडविड्थ के लीज कीमतों से प्रतिबिम्बित होता है बल्कि यह अन्तरराष्ट्रीय बाजार में आईआरयू कीमतों से भी प्रतिबिम्बित होता है। (उपयोग का अलोप्य अधिकार)

(ii) वास्तविक कीमतों अर्थात् रियायतों के लिए संशोधित सूचीबद्ध कीमत से तुलना

4. प्राधिकरण ने दूसरे देशों की बाजार कीमतों (आईपीएलसी लीज किराया) की तुलना भारत की आईपीएलसी हॉफ सर्किट के टैरिफों से करना आवश्यक समझा। इस प्रकार की सूचना के स्रोत का पता लगाना बहुत कठिन होता है। सामान्यतौर पर केबल सूचीबद्ध कीमत ही उपलब्ध होते हैं, जो प्रायः मार्केट की वास्तविक कीमतों में बहुत ज्यादा होते हैं। इस प्रयोजन के लिए, अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों से पूरी खोजबीन की गई और बाजार की कीमतों के संबंध में सूचना भी प्राप्त की गई।

नीचे की तालिका 1,2 और 3 (अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा) में रिपोर्ट किए गए आईपीएलसी लीज किरायों जो दिसम्बर, 2004 के दौरान चुनिंदा एशिया देशों में प्रचलित थे, का दूरस्थ देशों अर्थात् यूएसए के लिए भारत में आईपीएलसी के लिए प्रचलित टैरिफ तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है और इसके बाद जून, 2005 में वीएसएलएल द्वारा उस समय के मौजूद स्तर से भारत यूएस के आईपीएलसी ई–1 में 10% की कमी करने का प्रस्ताव किया गया था। इसके अलावा, टाटा इंडिकॉम इंडिया सिंगापुर केबल प्रणाली जोकि 15 अगस्त, 2005 से वीएसएलएल द्वारा चालू किया गया था, पर पैसिफिक मार्ग में आईपीएलसी टैरिफ में कमी को लागू किया गया (नीचे तालिका सं. 4,5,6 और 7 देखें) भारत और विदेशों, दोनों में बाजार स्थितियों के लिए इस कमी को भी पर्याप्त नहीं समझा गया था।

तालिका 1– आईपीएलसी (हॉफ सर्किट) ई1 कीमत की अंतरराष्ट्रीय तुलना

देश	वर्तमान कीमत (अमेरिकी डॉलर हजारों में)
जापान–यूएसए	23
दक्षिण कोरिया–यूएसए	23
हांगकांग–यूएसए	24
सिंगापुर–यूएसए	33
भारत–यूएसए	39

तालिका 2– आईपीएलसी (हॉफ सर्किट) डीएस–3 कीमत की अंतरराष्ट्रीय तुलना

देश	वर्तमान कीमत (अमेरिकी डॉलर हजारों में)
जापान–यूएसए	99
दक्षिण कोरिया–यूएसए	102
हांगकांग–यूएसए	124
सिंगापुर–यूएसए	174
भारत–यूएसए	656

तालिका 3– आईपीएलसी (हॉफ सर्किट) एसटीएम–3 कीमत की अंतरराष्ट्रीय तुलना

देश	वर्तमान कीमत (अमेरिकी डॉलर हजारों में)
जापान–यूएसए	191
दक्षिण कोरिया–यूएसए	229
हांगकांग–यूएसए	269
सिंगापुर–यूएसए*	346
भारत–यूएसए	1931

* DS-3 तथा STM-3 के टैरिफ कम होने के कारण सिंगापुर के E-1 टैरिफ ज्यादा हैं ।

नोटः 1) अन्य देशों में भी DS-3 तथा STM-1 के कीमत मल्टीपल भारत में बहुत कम हैं।

2) इसकी तुलना दिसम्बर, 2004 से की गई है।

3) भारत–यूएसए की कीमतों के अलग आकलन को ध्यान में रखते हुए वाल्यूम पर अधिकतम रियायत को हिसाब में लिया गया है।

स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय डाटा के लिए अरनेस्ट एंड यंग/टेलीजियोग्राफी ।

तालिका सं0 4 : भारत में आईपीएलसी (हॉफ सर्किट) लीज किराए–वीएसएनएल

(संगत अवधि के दौरान मौजूद विनियम दर लागू की गई है)

वर्ष	वार्षिक लीज किराया					
	ई1 (2 एमबीपीएस)		डीएस–3 (45 एमबीपीएस)		एसटीएम–1 (155 एमबीपीएस)	
	लाख रुपए में	अमेरिकी डॉलर ('000)	लाख रुपए में	अमेरिकी डॉलर ('000)	लाख रुपए में	अमेरिकी डॉलर ('000)
2002*	26	55	471	990	1365	2,868
2003#	30.8	67	471	1,027	1365	2,974
1.1.04#	23.7	52	445	980	1235	2,720
1.4.04#	21.3	49	401	913	1112	2,533
2005 (मई 2005 तक)#	20.2	46	361	820	1000	2,273
जून, 05#	18.2	41	307	698	800	1,818

नोटः प्रदान की गई रियायत को हिसाब में नहीं लिया गया है, क्योंकि यह विभिन्न मानदण्डों पर आधारित होता है।

* आईपीएलसी सेवाओं के टैरिफ, चाहे गंतव्य जो भी हो।

रि–स्टोरेबल श्रेणी तथा भारत से दूरस्थ गंतव्य के लिए लागू टैरिफ

तालिका सं0 5: आईपीएलसी (हॉफ सर्किट)* के लिए वीएसएनएल द्वारा दायर हाल के टैरिफ

(भारत–यूएस)	लाख रुपयों में	यूएस $ (0′000)
ई 1	11	25
डीएस 3	114	259
एसटीएम–1	330	750
(इंडिया–सिंगापुर)		
ई 1	10	22
डीएस 3	106	241
एसटीएम–1	310	705

नोट : ये टैरिफ पैसेफिक मार्ग से केवल टाटा इंडिकॉम इंडिया–सिंगापुर केबल प्रणाली पर ही लागू होंगे।

*15 अगस्त, 2005 से लागू।

तालिका सं0 6–वर्तमान आईपीएलसी (हॉफ सर्किट) टैरिफ–भारती इन्फोटेल

क्षमता	**वार्षिक लीज किराया**	
	लाख रुपए में	**अमेरिकी डॉलर**
ई 1	10	22
डीएस 3	176	399
एसटीएम–1	419	951

नोट 1. भारती इन्फोटेल की आईपीएलसी सेवाएं केवल नॉन–रिस्टोरेबल श्रेणी के लिए है (यथा–संसूचित)

2. उक्त टैरिफ भारत से दूरस्थ गंतव्य के लिए है।

3. प्रदान की गई रियायत को हिसाब में नहीं लिया गया है क्योंकि यह विभिन्न मानदण्डों पर निर्भर होता है।

4. विनिमय दर : 1 अमेरिकी डॉलर = 44रु0

तालिका 7–वर्तमान आईपीएलसी (हॉफ सर्किट) टैरिफ–रिलांयस इन्फोकॉम

क्षमता	वार्षिक लीज किराया	
	लाख रुपए में	अमेरिकी डॉलर (000)
ई 1	(पूर्ण सर्किट टैरिफ 70 लाख रूपए)	(पूर्ण सर्किट टैरिफ 159)
डीएस 3	427	972
एसटीएम–1	1238	2815

<u>नोट</u> 1. उपर्युक्त टैरिफ सभी गंतव्यों पर लागू है।

2. प्रदान की गई रियायत को हिसाब में नहीं लिया गया है।

5. अन्तरराष्ट्रीय बेंचमार्क के विश्लेषण से पता चलता है कि भारतीय आईपीएलसी की कीमत तुलनात्मक बाजार की कीमतों, खासतौर पर उच्चतर बैंडविड्थ सर्किटों की कीमतों से काफी ज्यादा है। अतः एशिया के बहुत से देशों, जिनमें से कुछ देश ग्लोबल बिजनेस प्रासेसिंग ऑपरेशन बिजनेस में भारत के प्रतियोगी हैं, से तुलना करने पर यह स्पष्ट है कि अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ की भारत में प्रतिस्पर्धी कीमत नहीं है। ये कीमतें ब्राडबैंड की लागत का अभिन्न अंग हैं और इस कठिनाई दूर करने की किसी नीति के संबंध में और भारत में ब्राडबैंड के विकास, खासतौर पर ग्रामीण भारत मे ब्राडबैंड के विकास के लिए इस पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए। लागत और उचित लाभ के आधार पर उपर्युक्त के संदर्भ में कीमतों का विनियमन करना आवश्यक हो जाता है।

6. अतः ऊपर उल्लिखित प्रमाणों से पता चलता है कि भारत में आईपीएलसी के लिए बाजार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण अन्तरराष्ट्रीय बैंचमार्क की तुलना में ज्यादा कीमतें हैं। एक स्वतंत्र परामर्श एजेंसी (गार्टनर, आईएनसी 2004 'मार्केट फोकसःइन्टरनेशनल बैंडविड्थ प्राइसिंग ट्रेंडस, एशिया–पेस्फिक, 2004) द्वारा हाल की में किए गए एक अध्ययन से भी इस बात की पुष्टि होती है। एशिया–पेसेफिक में अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ बाजार के संबंध में गार्टनर के अध्ययन का निष्कर्ष नीचे प्रस्तुत किया जाता हैः

"अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ के लिए सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी बाजार हांगकांग, सिंगापुर, जापान, ताइवान तथा दक्षिण कोरिया हैं। सबसे कम प्रतिस्पर्धी बाजार इंडोनेशिया, भारत तथा मलेशिया हैं।"

अनुबंध 'क' का परिशिष्ट 4

1. आईपीएलसी कीमत निर्धारण पद्धति/गणना।

प्राधिकरण के पास काफी संख्या में लागत के दृष्टिकोण उपलब्ध थे लेकिन इसने उस दृष्टिकोण को अपनाने का विनिश्चय किया गया जोकि बाजार को कम झटका दे और जिसे बिना किसी रूकावट के अपनाया जा सके। यह पहल पूरी तरह पूर्व आबंटित लागत पर आधारित था। अन्य विकल्प थे :–

क. परिचालकों के पूर्व लागत का भारित औसत

ख. केबल प्रणाली की पूर्ण बदलाव लागत

ग. विश्व बाजार में हाल ही के अधिग्रहण पर आधारित कीमतों का निर्धारण

घ. फॉरवार्ड लुकिंग कास्ट के विभिन्न स्वरूप जैसे फोरवार्ड लूकिंग लम्बी दूरी के अन्तरराष्ट्रीय लागतें (एफएलएलआरआईसी)–अधिकांश विनियामक इसे अन्तरराष्ट्रीय रूप से उपयोग करते हैं जिससे टैरिफ काफी कम हो जाता है।

2. यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लागत आधारित टैरिफ, भारत में आईएलडीओएस द्वारा सबमेरीन केबल प्रणालियों के अधिग्रहण के लिए किए जाने वाले बहुत ही कम स्तर के निवेश/लागत पर आधारित नहीं है क्योंकि यह प्रति E 1 मौजूदा निवेश का अंश मात्र का ही परिचायक है। इन लागतों के इस्तेमाल के परिणामस्वरूप आईपीएलसी की लागत आधारित कीमत में भारी गिरावट होगी और यह अन्तरण अवधि के दौरान बाजार को कोई बड़ा धक्का पहुंचाए बिना लागत आधारित अधिकतम टैरिफ विनिर्दिष्ट करने के प्राधिकरण के प्रयासों के भी विरूद्ध होगा।

3. एक नए प्रवेशक ने दीर्धकालिक आधार पर केबल की लीजिंग के लिए उनके द्वारा भुगतान किए गए आईआरयू लीज किराए से संबंधित आंकड़े मुहैया कराए हैं। दूसरे नए प्रवेशक ने केबल लैंडिंग सुविधा के लिए किए गए निवेश तथा उसके द्वारा भुगतान किए गए आईआरयू लीज किराए के आंकड़े मुहैया कराए। इन आंकड़ों के आधार पर E 1 क्षमता के लिए लागत अनुमानों का पता लगाया गया है। इन्कमबेंट की पुरानी प्रणालियों में लगे निवेश के मामले में पुरानी लागत से संबंधित लागत अनुमान की तुलना में इन अनुमानों में भी बहुत की कम कीमत दी गई है। जैसा कि पहले कहा गया है प्राधिकरण ने बाजार को कोई बड़ा धक्का लगाए बिना खासतौर पर इन्कमबेंट को, कोई बड़ा धक्का लगाए बिना सुचारू अन्तरण करने का निर्णय लिया है, इसलिए अधिकतम टैरिफ के निर्धारण के लिए नए प्रवेशकों के लागत अनुमान को इस समय उपयुक्त नहीं समझा गया है।

4. प्राधिकरण ने यह नोट किया कि वीएसएनएल ने 2004 में चेन्नई तथा सिंगापुर के बीच नई केबल प्रणाली का और चेन्नई में लैंडिंग स्टेशन का निर्माण किया। यह केबल प्रणाली प्रचालन के लिए तैयार है। वीएसएनएल द्वारा स्थापित इस नए केबल प्रणाली के माध्यम से आईपीएलसी सेवा मुहैया कराने की लागत अनुमान, उनके द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों के आधार पर प्राप्त किए गए हैं। E 1 क्षमता के हिसाब से लागत का अनुमान प्राप्त करने के लिए क्षमता उपयोग के एक रेंज पर विचार किया गया और इन्कमबेंट द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत जानकारी के अनुसार जिसके लिए सापेक्ष रूप से क्षमता का कम उपयोग हिसाब में लिया गया है। प्राधिकरण ने पाया कि इनमें भी लागत आधारित टैरिफ, वीएसएनएल की अपनी पुरानी केबल प्रणालियों की पृथक लेखाओं से प्राप्त टैरिफ से काफी कम है। ऊपर उल्लिखित कारणों से प्राधिकरण इन अपेक्षाकृत कम लागतों पर भी बिल्कुल निर्भर नहीं कर रहा है। यहां तक कि वीएसएनएल के लिए भारित औसत लागत के लिए भी नहीं। इस प्रकार लागत आधारित टैरिफ में भी पर्याप्त बफर की व्यवस्था की गई है।

5. प्राधिकरण ने नोट किया कि सबसे अधिक विस्तृत सूचना इन्कमबेंट के पृथक लेखों से प्राप्त हुई और लागत आधारित अनुमान, विश्लेषण तथा विस्तृत जांच के बाद प्राप्त की गई। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है दूसरे आंकड़ों के आधार पर भी अनुमान लगाया गया और हमारे विश्लेषण में इनसे भी उपयोगी सहायता प्राप्त हुई तथा लागत आधारित टैरिफ, इन्कमबेंट के पृथक लेखों से निकाला गया। वैकल्पिक लागत सूचना पर आधारित अनुमान कम था तथा नियामक नीति के तौर पर विनियामक के लिए टैरिफ की अधिकतम सीमा के निर्धारण के लिए इस प्रकार की सूचना का इस्तेमाल करना उचित था। प्राधिकरण ने प्रणाली को कोई बड़ा धक्का न लगने तथा निर्दिष्ट अधिकतम सीमा में उपयुक्त बफर रखने के लिए इन वैकल्पिक कम अनुमानों का इस्तेमाल नहीं किया।

6. वीएसएनएल के डाटा के आधार पर प्राधिकरण द्वारा लागत के आकलन की पद्धति निम्नानुसार है :

- वीएसएनएल की आईपीएलसी गतिविधियों से संबंध में वर्ष 2003–04 के लिए लेखा पृथक्करण विनियमन और वार्षिक लेखे के अंतर्गत पृथक लेखों में लिए गए लागत डाटा का उपयोग किया गया था। इनका विभिन्न लेखांकन श्रेणियों में आबंटन किया गया था।

- परिचालनिक व्यय, पूंजीगत व्यय और ई–1 की संख्या का आकलन, इस डाटा और वीएसएनएल द्वारा सूचित क्षमता के आधार पर किया गया है।
- उक्त सूचना के परिणामस्वरूप प्रति ई–1 पूर्ण आबंटित लागत का आकलन किया गया।
- क्षमताओं के लिए मूल्य अनुपात को परामर्श प्रक्रिया के दौरान विभिन्न कारकों और डाटा की जांच के आधार पर निर्धारित किया गया। (ब्यौरे के लिए खण्ड 3 देखें)
- इसके बाद वीएसएनएल को होने वाली पूर्ण लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक दोहराई जाने वाली प्रक्रिया का उपयोग किया गया, जिसमें प्रति ई–1 पूर्ण आबंटित लागत और मूल्य अनुपात सेटों के इनपुटों का प्रयोग किया गया। उदाहरण के लिए प्रति ई–1 की औसत लागत का आकलन वीएसएनएल द्वारा उपयोग में लाए गए ई–1, डीएस–3

तथा एसटीएम–1 सर्किटों के एक निश्चित अनुपात में किया गया। प्रति ई–1 की उस कीमत स्तर पर कीमत वसूली सुनिश्चित करने के लिए उच्चरत क्षमताओं का कीमत अनुपात 1:21:63 करना अपेक्षित होगा, जो उच्चर क्षमताओं में ई–1 सर्किटों की संख्या के समान है परन्तु जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है क्षमताओं का कीमत अनुपात विभिन्न कारकों तथा परामर्श प्रक्रिया के दौरान जांच किए गए आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यही विधि का उपयोग करके यह सुनिश्चित करना होगा कि इस कीमत अनुपात पर पूरी लागत की वसूली हो जाए। इस विधि का उपयोग करके प्रति ई–1 सर्किट की कीमत 13 लाख रुपए निर्धारित की गई थी और प्रयुक्त क्षमता की कई परिदृश्यो मे जांच की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि इन परिदृश्यों में पूरी लागत की वसूली का मार्जिन उपलब्ध हो।

- इसके अलावा, सभी अवरों पर पूर्ण लागत की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कुछ क्षमता उपयोगिता और विभिन्न क्षमताओं की हिस्सेदारी में भिन्नता लाई गई थी (मार्किट के हाल के बदलाव को देखते हुए)।
- इसके बाद मार्किट डायनामिक्स और दोहराए जाने वाली विभिन्न परिदृश्यों के आधार पर मूल्य को निर्धारत किया गया, जिससे वीएसएनएल के लिए पूर्ण लागत वसूली पुनः सुनिश्चित हो गई।
- इसके अलावा, तुलनात्मक उद्‌देश्यों के लिए विभिन्न अन्य ऑपरेटरों और केबल प्रणाली की लागतों की समीक्षा की गई।
- निर्धारित अधिकतम सीमाएं अन्तरराष्ट्रीय बेंचमार्क से अभी भी ज्यादा है, जिसमें और कमी की गुजांइश है (नीचे तालिका संख्या 8 देखें)।

तालिका सं. 8 – आईपीएलसी कीमत (एशिया क्षेत्र), की ई–1 कीमतें, और कीमत मल्टीपल की अन्तरराष्ट्रीय तुलना

देश	**ई–1 मूल्य, यूएस डालर'000**	**डीएस–3 मूल्य यूएस डालर' मिलियन**	**एसटीएम–1 मूल्य यूएस डालर' मिलियन**	**कॉलमों का अनुपात (1):(2):(3)**
जपान	23	0.10	0.2	1:4:8
दक्षिण कोरिया	23	0.10	0.2	1:4:8
हांग–कांग	24	0.12	0.3	1:5:11
सिंगापुर*	33	0.17	0.3	1:5:11
भारत (सीलिंग फिक्सड) @रु.	29.55	0.24	0.68	1:8:23

अन्तरराष्ट्रीय डाटा का स्रोतः एर्नेस्ट और यंग/टेलीजियोग्राफी

नोटः यूएस डालर = 44 रु.

इसके साथ–साथ डीएस–3 और एसटीएम–1 के लिए निम्न मल्टीपल होने के कारण सिंगापुर के ई–1 कीमत का अधिक होगा।

7. अंततः लागत प्रक्रिया के दौरान बफर की अनुमति दी गई है जोकि पूंजी पर प्रतिफल के माध्यम से पहले से ही लाभ का मार्जीन प्राप्त होता है, जो वीएसएनएल द्वारा अलग से लेखा में अपने डब्ल्यूएसीसी के रूप किए गए दावों के मूल्य के बराबर है। व्याख्यात्मक ज्ञापन के मुख्य भाग में इसकी चर्चा भी गई है। अतः यह चर्चा दर्शाता है कि प्राधिकरण द्वारा आईपीएलसी के लिए निर्धारित किए गए टैरिफ में अपनाई गई पद्धति उपयोग में लाए गए डाटा स्रोत और विश्लेषण में पूरी पारदर्शिता बरती गई है।

अनुबंध 'क' का परिशिष्ट 5

देश में आईपीएलसी की विनियामक तथा प्रतिस्पर्धा की स्थिति इस प्रकार है :

देश	विनियम
आस्ट्रेलिया	1992 से 2001 के बीच राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय लीज लाइन CPI-X% कीमत नियंत्रण के अंतर्गत थे। जब इन्टरनेशनल लीज्ड लाइन के बाजार को प्रतिस्पर्धी समझा गया तब बाद में इसे हटा दिया गया।
चीन	सभी लीज लाइनों की दरें सरकार द्वारा निर्धारित हैं। आगे कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।
हांगकांग	अप्रैल, 2001 में फिक्सड टेलीकॉम नेटवर्क सेवाएं मुहैया कराने के लिए कैरियर लाइसेंस प्रणाली लागू की गई और प्रमुख ऑपरेटरों के लिए अधिकतम सीमा का प्रावधान किया गया। REACH एकमात्र प्रमुख ऑपरेटर था। मार्च, 2002 में ओएफटीए ने घोषित किया कि REACH प्रमुख ऑपरेटरा नहीं रह गया है इसलिए अधिकतम कीमत हटा दी गई है।
आयरलैंड	कामरेग, इस समय आईपीएलसी के बाजार के संदर्भ के परामर्श प्रक्रिया का काम कर रहा है। कामरेग का इस समय विश्वास है कि आईपीएलसी के लिए घरेलू बाजार प्रतिस्पर्धी है और EIRCOM के सभी दायित्वों, जिसमें इस समय लागत, तथा प्रतिस्पर्धियों को गैर–भेदभावपूर्ण अभिगम्यता प्रदान करना भी शामिल है, को वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है।
जापान	जापान में ऑपरेटरों को टाइप I तथा टाइप II के रूप में परिभाषित किया गया है। टाइप–I के ऑपरेटरों पर अधिकतम कीमत निर्धारण की व्यवस्था लागू है और टैरिफ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लागू करने

	से पूर्व विनियामक से अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित है। सभी विनियमन 2001 में समाप्त कर दिए गए क्योंकि विनियामक ने यह समझा कि DPLCs तथा IPLCs के लिए बाजार अब प्रतिस्पर्धी हो गया है।
सिंगापुर	सिंगापुर में प्रमुख लाइसेंसधारी को विनियामक के पास अनुमोदन के लिए टैरिफ दायर करने होते हैं। सिंगेटेल, आईपीएलसी का प्रमुख प्रदाता माना जाता है और इसलिए उसे आईडीए के पास सभी टैरिफ संशोधन दायर करने होते हैं और आईडीए को यह आकलित करना होता है कि क्या ये टैरिफ नियमानुकूल हैं और यह जांच करनी होती है कि क्या ये भेदभावपूर्ण तो नहीं है और क्या ये लागत आधारित हैं। इसके अलावा, 2001 में आईडीए ने व्यवस्था दी कि वैकल्पिक ऑपरेटर अपने इक्यूपमेंट सिंगटेल के लैंडिंग स्टेशन पर रख सकते हैं। अप्रैल 2002 में इसमें संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि सिंगटेल को वैकल्पिक ऑपरेटरों को कनेक्शन मुहैया कराना जरूरी है, आईडीए का दृष्टिकोण अन्तरसंयोजन अधिकार लागू करना तथा बाजार को फुटकर टैरिफ निर्धारित करने की अनुमति देना है।
द0 कोरिया	अन्तरराष्ट्रीय लीज्ड लाइन मार्केट में 14 लाइसेंसधारी हैं – आईपीएलसी के लिए बाजार को प्रतिस्पर्धी माना जाता है।
यूनाइटेड किंगडम	बाजार को प्रतिस्पर्धी समझा जाता है – कोई विनियमन नहीं
संयुक्त राज्य अमेरिका	बाजार को प्रतिस्पर्धी माना जाता है – कोई विनियमन नहीं

स्रोतः एर्नास्ट एण्ड यंग